

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 जून, 2005

खण्ड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 9 जून 2005

पृष्ठ संख्या

सदस्यो द्वारा भापथ/प्रतिज्ञान	(1)1
भाोक प्रस्ताव	(1)1
भापथ/प्रतिज्ञान	(1)10
स्थगन प्रस्ताव की सूचना/वाक आउट	(1)11
तरांकित प्र न एवं उत्तर	(1)13

नियमो 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तरांकित प्र नो के लिखित उत्तर	(1)30
अतरांकित प्र न एवं उत्तर	(1)33
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	(1)38
(क) अध्यक्ष द्वारा	(1)38
(i) चेयरपर्सन्ज के नामो की सूची	(1)38
(ii) सदस्यो द्वारा त्याग पत्र	(1)38
(iii) अनुपस्थित की सूचना	(1)39
(ख) सचिव द्वारा	(1)39
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलो सम्बन्धी	(1)39
नियम 21 के अधीन प्रस्ताव	(1)39
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पे ट करना	(1)40
सदन के मेज पर रखे गए पुन रखे गए कागज	(1)42
वर्ष 2005-06 के बजट अनुमान प्रस्तुत करना	(1)45

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 9 जून, 2004

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार एच0एस0 चट्टा) ने अध्यक्षता की।

सदस्यो द्वारा भाषण/प्रतिज्ञान

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I call upon Shri Bhupinder Singh, Hooda, a members who has returned in the Bye-election from 29, Kilo Assembly Contituency and Smt. Kiran Chaudhary, a members, who has returned in the Bye-election from 67, Tosham Assembly Constituency of the Haryana Legislative Assembly held on 2nd June, 2005 to subscribe oath/affirmation of allegiance to the Constitution of India.

I will also reques them for siging the Roll of Members, pleaced on the Secretary's table after making subscibe oath/affirmation of allegiance.

(At this stage Shri Bhupender Singh Hooda and Smt. Kiran Chaudhary, subscribed oath/affirmation of allegiance to the Constitution of India.)

भाोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Chife Minister will make obituary referenes.

मुख्यमंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवे तन और इस अधिवे तन के बीच मे से हमारे बहुत

प्रमुख सदस्य, स्वतन्त्रता सेनानी एक एक करके हमें छोड़ कर जा रहे हैं। इसके साथ ही इस विधान सभा के दो सदस्य भी जो मंत्री मंडल के सदस्य थे, हमें छोड़कर चले गए हैं। उनके चले जाने से जो नुकसान हुआ है वह बर्दाश्त करना संभव नहीं है। उनको उनके परिवार वालों ने, हरियाणा की जनता ने और हमने भी खोया है। इसी प्रकार से श्री सुनील दत्त भी जो हरियाणा के ही थे वे हमें छोड़ कर चले गए। अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से भाोक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्री सुनील दत्त, एक प्रसिद्ध अभिनेता एवम केन्द्रीय मंत्री

यह सदन एक प्रसिद्ध अभिनेता एवम केन्द्रीय मंत्री श्री सुनील दत्त के 25 मई, 2005 को हुए दुःखद व आकस्मिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 6 जून, 1929 को हुआ। उन्हें जिला यमुनानगर के गांव मडोली से विशेष लगाव था, क्योंकि उनका परिवार देश के विभाजन उपरान्त इस गांव में आ बसा था। वे सच्चे देशभक्त एवम धर्मनिर्पेक्षता की प्रतिमूर्ति थे। पण्डित जवाहरलाल नेहरू के आर्षिवाद से श्री सुनील दत्त व उनकी पत्नी श्रीमती नरगिस ने अजन्ता आर्ट्स वैलफेयर ट्रूप का गठन किया ता 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 एमव 1971 के भारत पाक युद्धों के दौरान भारतीय सेना के जवानों का मनोरंजन करने के लिए देश की सीमाओं पर गए।

वे 1984, 1989, 1991, 1999 तथा 2004 में लोक सभा के लिए चुने गए। वे 2004 में केन्द्रीय खेल एवम मामलों के मंत्री बने

और निधन के समय तक इस पद पर रहे। मंत्री के रूप में वे खेलों के स्तर पर सुधार तथा खिलाड़ियों के कल्याण को समर्पित थे। ये युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे।

उन्हें जितना पर्दे पर अभिनय करने के लिए याद किया जाएगा। उतना ही भ्रान्ति और साम्प्रदायिक सदभाव के लिए मुहिम चलाने तथा कैंसर पीड़ितों की सेवा के लिए भी याद किया जाएगा। उन्होंने अपना फिल्मी जीवन 1955 में फिल्म 'रेलवे प्लेटफार्म' से शुरू किया तथा 1957 में कालजयी फिल्म 'मदर इण्डिया' से वे अपने अभियान के चरम पर पहुंचे। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों को अभिभूत किया। उन्होंने अनेक सफल फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनकी पत्नी नरगिस के 1981 में कैंसर के कारण हुए निधन के बाद उन्होंने अपना जीवन कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए धन जुटाने एवम सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1987 में मुंबई से अमृतसर तक पदयात्रा की तथा स्वर्ण मन्दिर में भ्रान्ति के लिए अरदास की। इसके एक वर्ष बाद वे परमाणु हथियारों के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज करने के लिए नागासाकी तथा हीरोशिमा गए।

उन्होंने अपने जीवन में जो भी भूमिका निभाई वह बेजोड़ थी। उन्हें अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया, जिनमें फिल्म फेयर बैस्ट एक्टर अवार्ड, 1968 में पद्मश्री, 1988 में अंतर्राष्ट्रीय भ्रान्ति, साम्प्रदायिक सदभाव, एकता एवम राष्ट्रीय अखंडता, के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान अवार्ड, 1997 में

राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड, 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड तथा 2004 में हरियाणा गौरव अवार्ड भामिल है। व्यक्तिगत तौर पर भी वे मेरे मित्र थे और लोक सभा में भी वे मेरे साथी रहे। उनका स्वभाव सबको साथ लेकर चलने का था।

उनके निधन से भारत विशोक हरियाणा अपने एक महान सपूत, एक प्रसिद्ध समाजसेवी, अनुभवी सांसद, सुप्रसिद्ध अभिनेता एवम योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाग्य संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदन प्रकट करता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह हरियाणा के मंत्री

यह सदन हरियाणा के मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक हृदय विदाकर हेलीकाप्टर दुर्घटना में 31 मार्च, 2005 को हुए दुःखद व आकस्मिक निधन पर गहरा भाग्य प्रकट करता है।

उनका जन्म 25 जुलाई, 1946 को हुआ। हरियाणा की राजनीति के चमकते सितारे श्री सुरेन्द्र सिंह ने राजनीति को पाठ अपने पिता श्री बसी लाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा की छत्रछाया में सीखा। वे प्रजातान्त्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने कठोर परिश्रम, सघर्ष व लगन के बलबूते पर राज्य एवम राष्ट्र की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान बनाया। वे 1977 से 1986 तक हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे और 1982-83 के दौरान मंत्री रहे। वे 1986 से 1992 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वे दो बार

1996 तथा 1998 में लोकसभा के लिये चुने गये। वे अनेक संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे 2005 में पुनः हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और मंत्री बने।

वे किसानों की समस्याओं को भली भाँति समझते थे तथा कृषि और किसान से उन्हें विशेष लगाव था। उनके निधन से कुछ ही देर पहले उनकी कलम से निकला अन्तिम आदेश भी किसानों के हित में था।

दृढ़ निश्चयी एवम साहसी श्री सुरेन्द्र सिंह हरियाणा के विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध थे तथा इसके लिए उनका एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। वे ईमानदार, सादगी एवम अनुशासन की प्रतिमूर्ति थे। वे युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत थे, जिन्हें उनसे बहुत आशाएँ थीं लोकसभा में साथ साथ सदस्य रहे और जब भी लोकसभा में कोई सीरियस मामला होता था तो स्पीकर साहब, उनको कहते थे ताकि वे हाउस में कोई ऐसी बात कहते थे जिससे कि हाउस लाइट हो जाता था तो जो लोकसभा में खिचाव होता था उसको दूर करने में सहायक रहे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवम योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है यह सदन दिवंगत के भोक्त संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदन प्रकट करता है।

श्री ओम प्रकाश जीन्दल, हरियाणा के मंत्री

यह सदन हरियाण के मंत्री श्री ओम प्रकाश जिंदल के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक हृदय विदाकर हेलीकाप्टर दुर्घटना में 31 मार्च, 2005 को हुए दुःखद व आकस्मिक निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

मैक ऑफ स्टील के नाम से प्रसिद्ध श्री ओम प्रकाश जिंदल का जन्म 7 अगस्त, 1930 को हुआ। उन्होंने एक छोटे उद्यमी से औद्योगिक जीवन की भुर्राआत की और वे कठोर परिश्रम के बलबूते पर एक सफल उद्योगपति बने। आज जिंदल औद्योगिक समूह का न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में नाम है। उनकी यह सोच थी भारत, उद्योग के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। वे उद्योग एवम कृषि क्षेत्र में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विज्ञान व का अत्याधुनिक प्रौद्योगिक का प्रयोग करने के पक्षधर थे।

वे एक सफल उद्योगपति होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। वे 1991 तथा 2000 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे 1996 में लोक सभा के लिये भी चुने गये। वे 2005 में पुनः हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और मंत्री बने।

वे व्यवसाय व राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद भी धार्मिक और सामाजिक कार्यों में पूर्ण रूचि लेते थे। वे आर्थिक एवम सामाजिक समानता के पक्षधर थे और इस दिशा में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उनका जीवन उद्योगपति, समाजसेवी एवम एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में केवल हरियाणा के लोगों अपितु पूरे देश के लिए प्रेरणास्त्रोत रहेगा। मेरे को

सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोकसभा में भी साथ रहे और विधानसभा के भी साथ रहे, हर मामले पर जो भी जनकल्याण की बात होती थी उसमें वे पूरा सहयोग करते थे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद एवम योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाग्य संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदन प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी

यह सदन उन श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा भाग्य प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं:—

1. श्री बी०के० भारदा, भिवानी।
2. श्री भयोदत, गांव कासनी कंला, जिला भिवानी।
3. श्री जगमाल सिंह, गांव पुनसिका, जिला रेवाड़ी।
4. श्री भीराम, गांव कितलाना, जिला भिवानी।
5. श्री सूरत सिंह, गांव सच्चाखेडा, जिला जीन्द।
6. श्री घनश्याम दास, गांव भाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र।
7. श्री पाखर सिंह विर्क, गांव सलेमपुरी, जिला

फतेहबाद।

8. श्री सुन्दर सिंह, गांव रायपुर, जिला सोनीपत।
9. श्री रामस्वरूप, तिलक नगर, रोहतक।
10. श्री सूबे सिंह, गांव झाडली, जिला झज्जर।
11. श्री करतार सिंह, गांव झोरनाली (ढाणी खोबा),
जिला सिरसा।
12. रतन सिंह, गांव सैम्पल, जिला रोहतक।
13. श्री बुट्टी राम, गांव खेडी होियापुर, जिला
झज्जर।
14. श्री प्रभुदयाल, गांव निमोठ, जिला रेवाडी।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को भात भात नमन करता है और इनके भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदन प्रकट करता है।

हरियाणा के भाहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना आश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने हमारे एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं:—

1. सुबेदार कर्मचन्द, गांव दमदमा, जिला गुडगांव।
2. उप निरीक्षक ई वर सिंह, गांव बहहाणा, जिला
झज्जर।

3. हवलदार मालाराम, गांव सिसोठ ढाणी टेकचन्द,
जिला महेन्द्रगढ ।

4. हवलदार रिसाल सिंह, सिवानी, जिला भिवानी ।

5. हवलदार श्रीपाल, गांव भाटला, जिला हिसार ।

6. हवलदार रणबीर सिंह, गांव कितलाना, जिला
भिवानी ।

7. हवलदार धर्मपाल, नारनौंद, जिला हिसार ।

8. हवलदार सूरजभान, गांव चरखी, जिला भिवानी ।

9. सिपाही प्रताप सिंह, गांव बापोडा, जिला भिवानी ।

10. सिपाही भयामलाल, गांव चन्दू ढाणी ओमनगर
जिला गुडगांव ।

11. सिपाही सुरेन्द्र सिंह, गांव इमलोटा, जिला भिवानी ।

12. सिपाही कृष्ण कुमार, गांव कुरलन, जिला करनाल ।

13. सिपाही जयवीर, गांव किठाना, जिला कैथल ।

14. सिपाही उमेद सिंह, गांव लाड, जिला भिवानी ।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को भात भात
नमन करता है और इनके भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति
अपनी हार्दिक संवेदन प्रकट करता है ।

यह सदन

संसद श्री अवतार सिंह भडाना के भाई तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री रामकिान के ससुर, श्री संत सिंह तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री नरेण मलिक की भाभी श्रीमती अनीता देवी के दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदन प्रकट करता है।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सर, जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा है उसमें अपने आपको जोड़ने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर सर, श्री सुनील दत्त का व्यक्तित्व कोई भाब्दो का मोहताज नहीं था, हम सबको इस बात का हमें या फरख रहेगा कि उन्होंने हरियाणा की मिट्टी में जन्म लिया। श्री सुनील दत्त ने कई प्रकार के रोल अदा किए। एक राजनेता के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर, एक समाजसेवी के तौर पर और सबसे महत्वपूर्ण भान्ति के दूत के तौर पर भाायद इसीलिए पूरा हिन्दुस्तान उन्हें एक भान्ति के दूत के नाम से जानता था। जब जब सुनील दत्त का नाम लिया जाता था, भान्ति का दूत लब्ज अपने आप यकायक सभी दला, सभी व्यक्तियों और सभी धर्मों के लोगों के मुखर्विन्द पर आ जाता था। चाहे बाम्बे में दंगों की बात हो, चाहे पजाब में हिंसा की बात हो, चाहे परमाणु अस्त्रों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी, देणव्यापी और विणव्यापी युद्ध चलाने की बात हो, चाहे आपसी सामन्जस्य और सद्भाव बढ़ाने की बात हो और चाहे गुजरात दंगों के बाद जगह जगह जाकर जरूरतमन्दों के आंसु पोछने की बात हो। भान्ति और

सद्भाव का सन्देश पूरे देश के अन्दर और पूरे विश्व में ले जाने की बात हो, सुनील दत्त जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह सच है कि उनके जाने से पूरे राष्ट्र को ऐसी कमी रहेगी जो ने केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बल्कि पूरा भारत देश कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर पायेगा। हम सभी साथी ही नहीं बल्कि यह पूरा सदन उनको श्रद्धाजलि देता है।

स्पीकर सर, इस सदन के माननीय सदस्य और सरकार में मंत्री चौधरी सुरेन्द्र सिंह का आकस्मिक निधन हम सभी जानते हैं कि हेलीकाप्टर दुर्घटना में हुआ। स्पीकर सर, चौधरी सुरेन्द्र सिंह का व्यक्तित्व भी भाबू का मोहताज नहीं था और न ही राजनीति दायरों को मोहताज था। स्पीकर सर, आपने एक से अधिक बार उनके साथ बतौर विधान सभा के सदस्य और बतौर विधान सभा के अध्यक्ष तौर पर कार्य किया है। मुझे सौभाग्य प्राप्त था कि वे वही पर बैठते थे। सदन में कोई भी बात हो, हमें उनका कन्ट्रीब्यूशन रचनात्मक होता था, सहयोग वाला होता था और बार बार वे विपक्ष के सदस्यों को एक ही बात कहा करते थे कि मुझे आज भी याद है कि हम किसी की आवाज को दबायेगे नहीं बल्कि आप आलोचना कीजिए हम उसका स्वागत करेंगे। चौधरी सुरेन्द्र सिंह का जो व्यक्तित्व था जो उनका उदार हृदय था, सहजता से सभी दलों के लोगों को सभी विचारधारा के लोगों को अपने आप में वह मोह होता था। उनका मुस्कराता हुआ चेहरा जब जब भी हम इस सदन के अन्दर आएंगे तो वह हमें दिखाई देता महसूस होगा। हम समस्या को बड़ी सहजता से लेने वाला चेहरा, हम मुश्किल को मिनटों में चुटकियों में हल करने वाला

चेहतरा मुझे नही लगता कि हम मे से कोई सदस्य हो यहा हरियाणा या पूरे प्रदे 1 का कोई भी निवासी हो जिनका उनको साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुडाव रहा हो, वह उनको भुला नही पाएगा। हमे जंहा इस बात का दुख है कि आज वे हमारे बीच मे नही है और उनके निधन से होने वाले नुकसान की हम भरपाई नही कर पाएगे। इसके साथ साथ हमे इस बात की खु ी भी है कि उस परिपाटी को, उसी बात को लेकर उसी म ाल को लेकर, उसी भामां को लेकर जो उन्होने जलाई थी उनकी धर्मपत्नी जी आज हमारे बीच मे है। हम सब का यह प्रयास रहेगा कि जो उन्होने खेतीबाडी के लिए, नौजवानो के लिए या दूसरो कामो के लिए बुनियाद रखी थी, यह सदन उन नीतियो पर, उन कार्यों पर न केवल विचार विर्म 1 करे बल्कि उनको क्रियान्वित करने की कोि 1 1 करे। खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि व्यक्तिगत तौर से जिनका उनके साथ जुडांव रहा, मुझे नही लगता कि वे उनको भूला पाएगे। यह सदन या प्रान्त उनके निधन से होने वाले नुकसान को कभी पूरा नही कर पाएगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे दूसरे वरिष्ठ मंत्री श्री ओमप्रका 1 जिन्दल जी, जिनको सब बाउजी के नाम से पुकारते थे। वे आज हमारे बीच मे नही है। जब जब जिन्दल साहब के पास भिन्न भिन्न राजनैतिक दलो के लोग और भिन्न भिन्न विचार धाराओ के लोग जाते थे तो वे एक ही बात कहते थे, ठीक है कि राजनैतिक मे हम एक तरफ है, आज दूसरी तरफ है, हमारे और आपके वैचारिक मतभेद हो सकते है। लेकिन हमे 11 कहते थे कि समाज और परस्परिक रि ते राजनीतिक विरोध से परे है उन्होने

यह साबित कर के दिखाया कि किस तरह से एक साधारण परिवार में रहने वाला, छोटे से भाहर में पैदा होने वाला व्यक्ति अपने हाथ से कार्य करके हरियाणा का नाम न केवल औद्योगिक जगत में बल्कि समाज और राजनीतिक जगत में ऊंचा कर सकता है। उन्होंने हमको यह भी दिखाया कि किस प्रकार राजनीति में नई दिशा लाई जा सकती है। उन्होंने हमको यह भी दिखाया कि किस प्रकार से नौजवान और बुजुर्ग को रास्ता दिखाया जा सकता है। उनकी धर्मपत्नी आज हमारे बीच सदस्या हैं। हमें आशा है नहीं बल्कि विश्वास है कि हरियाणा में उद्योग के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में जिस क्रांति का सपना वे देखते थे, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह सरकार उसको जारी रखेगी।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों, और हरियाणा के भाहीदों में विशेष तौर से हमारे साथी श्री राम किशन जी और हमारे साथी श्री नरेन्द्रा के परिवार के सदस्यों का निधन हुआ है। मैं इनके परिवार की भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। कि वे इन सभी को जो आज हमारे बीच में नहीं हैं अपने चरणों में स्थान दें।

डा० सुनील इन्दौरा (ऐलनाबाद, एस०सी०): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो भावुक प्रस्ताव में पेश किया गया है मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम याद करें तो जब हम छोटे बच्चे होते थे। तो सुनील दत्त की फिल्में देखा करते थे। हमारे दिल में बड़ा चाव होता था किसी तरह से फिल्मों में कलाकारी करते हैं। उस वक्त हम बड़े नादान

होते थे और स्कूल छोड़कर उनकी फिल्म देखने जाया करते थे। जिस तरह से उन्होंने फिल्मों में काम किया उसी तरह का काम बाद में हमने उनकी व्यावहारिक जिन्दगी में महसूस किया। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ बतौर सांसद रहा हूँ। मैं उनसे मिलता था तो मुझे बचपन की बातें याद आ जाया करती थीं। कि कैसे मैं उनको परदे पर देखता था और कैसे अब उनको असलियत से देख रहा हूँ। उनका स्वभाव बड़ा सौम्य था। वे हर बात को अच्छे ढंग से पढ़ा करते थे। वे कोई पार्टी नहीं देखते थे। वे सबके साथ बिना भेदभाव के मिलते थे। उनका काम समाज में सुधार के तौर पर बदलावा लाना था। वे अच्छे समाज सुधारक थे, अच्छे राष्ट्रीय नेता थे, और अच्छे मंत्री थे, वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनके निधन पर मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए उनकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाएँ जोड़ता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे मंत्री चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी एक ऐसे हादसे का शिकार हुए जिसको हरियाणा के लोग भूला नहीं सकते। मुझे आज भी याद है कि वे कैसे व्यक्ति थे? स्पीकर साहब, मेरा और उनका पारिवारिक रिश्ता रहा है। मैं भी भिवानी जिले का हूँ। उनका गाँव गोलागढ़ है और मेरा गाँव गिगनऊ है। जब पहली बार मैं पार्लियामेंट में गया था तो उन्होंने बड़े भाई की तरह मुझे आर्म्बिवाद दिया और कहा कि बहुत अच्छा लगा कि एक गरीब परिवार का साथी हमारे बीच में आया है। अध्यक्ष महोदय, वे लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। और अपनी बात बड़े हसमुख ढंग से कहते थे और दूसरी बात भी बड़ी सहजता से

सुनते थे। पार्लियामेंट में जब भी कोई बात में कहता था तो बाहर आने पर वे मुझे कहते कि आपने बहुत अच्छी बात कही। जब हम पार्लियामेंटरी से बाहर आकर एक साथ बैठकर चाय पीते थे तो उस समय हम आपस में राजनीतिक और अपने घर परिवार की चर्चा किया करते थे। उनके निधन के समय जब मैं उनके घर पर गया तो मैं अपने आपको रोक नहीं पाया। मेरी आंखों में आसू आ गये। चौधरी रणवीर सिंह महेन्द्रा जो उनके भाई यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि उनके निधन से मैंने सचमूच में अपने बड़े भाई को खो दिया है। चौधरी सुरेन्द्र सिंह की मृत्यु को न तो मैं भुला पाऊँगा और न यह सचमूच भुला पाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक यहाँ पर स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिंदल जी का जिकर किया गया है मैं बताना चाहूँगा कि उनके साथ मेरा लम्बा चौड़ा रिस्ता नहीं रहा। उनके बारे में मैंने यह सुन रखा था कि आवगभगत बहुत अच्छी करते हैं। जब पहले दफा मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य अपने नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ मिला मालूम हुआ कि उनके बारे में जो सुन रखा था वे उससे भी अच्छी आवगभगत करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं अपने नेता के साथ एक दफा सुबह सुबह उनके घर गया था। उस समय वे अपने घर के बाहर हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे यह चीज खाओ, वह चीज खाओ। उसके बाद मुझे कई दफा उनसे मिलने का अवसर मिला कभी सता के गलियारों में तो अवसर मिलता था। वे बहुत अच्छे इंसान थे। उनके निधन से हमने एक

बड़े उद्योगपति अच्छे राजनेता और अच्छे इंसान को खो दिया है।
उन्हे हम सदा याद करेगे।

इसके साथ साथ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी वे भी आज हमारे बीच में नहीं हैं उनके निधन से भी मुझे गहरा दुख है। उनके नाम पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं अपने मान स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धाजली देता हूँ और भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

इसके साथ साथ मेरे साथी सांसद श्री अवतार सिंह भडाना के भाई तथा हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री राम किशन के ससुर श्री सतं सिंह, हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री नरेन्द्र मलिक की भाभ्जी श्रीमती अनिता देवी के निधन पर मैं गहरा भाोक प्रकट करता हूँ। अतः मैं पिछले अधिवेशन से लेकर अब तक जो राजनेता, समाजसेवी, सांसद, स्वतंत्रता सेनानी और भाहीद हमारे बीच में नहीं रहे उन सबके भाोक संतप्त परिवारों को अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से और हम सबकी तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी ने इतना जरूर कहूंगा कि भाई सुरेन्द्र सिंह जी और श्री ओम प्रकाश जिंदल जी पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी में बहुत विश्वास रखते थे। उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजली उनको यही होगा कि हम उनके दिखाये हुए रास्ते पर सरकार का काम करके और यह सदन चलें। धन्यवाद

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): स्पीकार सर, मुख्यमंत्री जी ने सदन के जो भाोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके साथ मैं अपने को और अपनी पार्टी को जोडता हूँ और भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। जहां तक सुनील दत्त जी का सवाल है अभी उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि वे बहुत बड़े भााति के दूत थे, नेक इसांन थे और दे आ भक्त थे। उनके निधन से सारा दे आ दुखी है। उनकी मौत से उनकी कमी हमें सदा याद रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनके भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक भाई सुरेन्द्र सिंह जी का सवाल है उस बारे में बताना चाहूंगा कि हम दोनों एक साथ पढते थे। जब विमान दुर्घटना में उनकी और श्री ओम प्रका आ जिंदल जी की मुत्यु की खबर झटका लगा। चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी स्कूल के दिनों में मेरे साथ क्रिकेट खेला करते थे। और मैं उस समय कैप्टन होता था। वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन हमारे राजनैतिक विचार नहीं मिले और बहुत साल तक हम दूर रहे। मैं कांग्रेस पार्टी में भी रहा, लेकिन जब ये दोबारा एम0एल0ए0 नकर आए तो वे मुझे मिले और कहने लगे कि अब हम मिल कर इकट्ठे चलेंगे। उस समय वहां पर और भी कई साथी थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप गौतम जी को जानते हैं तो उन्होंने कहा कि हां बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ हम इकट्ठे क्रिकेट खेला करते थे। इस बात पर वे मुझे कहने लगे कि क्या यह बात कहनी जरूरी थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे क्या पता था कि यह सारी बातें यूँ ही

यादगार के रूप में रह जाएगी। इसके कुछ दिन बाद जब हवाई हादसे में उनका देहान्त हुआ तो मुझे बड़ा झटका लगा।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक जिन्दल साहब की बात है, श्री ओम प्रकाश जिंदल जी की पार्टी और हमारी पार्टी अलग थी लेकिन 10 दिन में, 15 दिन में 20 दिन में उनका फोन मेरे पास आ जाता था। हर ईदू पर कोई बात होती थी तो वे मेरे से सलाह कर लेते थे। हालांकि मैं बीजेपी में हूँ और वे कांग्रेस पार्टी में थे फिर भी मेरे साथ उनके बहुत ही अच्छे सम्बन्ध थे। वे बहुत ही नेक इन्सान थे, बड़े दिलैर आदमी थे और बहुत ही पक्के इरादे के व्यक्ति थे। उनकी मौत की जब मुझे खबर मिली तो मुझे एक दम करण्ट सा लगा और सहसा इस पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा भूय पैदा हो गया है और हरियाणा की राजनीति में उनकी मृत्यु का बहुत प्रभाव पड़ेगा उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और अपनी पार्टी की तरफ से तथा अपनी तरफ से दुख प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, जितने भी स्वतन्त्रता सेनानी हमारे बीच में चले गए हैं, उनके चले जाने का भी मुझे बहुत दुख है। स्वतन्त्रता सेनानी इस देश की धरोहर हैं हम सभी को उनके चले जाने का बहुत भारी दुख है लेकिन यह संसार नवर है, जो इस धरती पर आया है उसको जाना ही पड़ेगा, लेकिन उनके चले जाने का बहुत भारी दुखी है। उनके परिवारों के प्रति भी मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की संवेदना प्रकट करता हूँ और जो साथी हमारे बीच में चले गए हैं, उनके जाने का बहुत दुख है। भारदा जी मेरे बहुत

ही पर्सनल जानने वाले थे। वे फ्रीडम थे और बहुत ही उच्च कोटि के पत्रकार थे। उनकी मौत का भी बहुत ही अफसोस है। भाई नरे । मलिक के भाई की मिसेज की जिन हालात में मृत्यु हुई उसका भी बड़ा भारी दुख और हम को उनके निधन का बहुत भारी अफसोस है उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और अपनी पार्टी की तरफ से तथा अपनी तरफ से दुख प्रकट करता हूँ।

श्री जय सिंह राणा (नीलोखेडी): अध्यक्ष महोदय, जो वायुयान की दुर्घटना हुई जिसमें हमारे दो मन्त्रियों का निधन हो गया था उस हवाई हवाई में उस हवाई जहाज के पायलट कर्नल टी०एफ० चौहान की भी मृत्यु हो गई है मेरा सरकार से निवेदन है कि उनका नाम भी इन भाग प्रस्तावों में जोड़ लिया जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा: अध्यक्ष महादेय, उनका नाम भी इन भाग प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है आनरेबल मैम्बर, ठीक है, आज हम हाउस में बड़े दुखी हृदय के साथ बैठे हैं। हमारे वे परम मित्र, चौधरी सुरेन्द्र सिंह और जिन्दल साहब हमें छोड़ कर चले गए हैं जिनको हम यह समझते हैं कि आने वाला हरियाणा है। जिन्दल साहब यह कहा करते थे कि दो साल में हरियाणा में बिजली की कमी नहीं रहेगी और सुरेन्द्र सिंह जी ने यह कहा करते थे कि दो साल के बाद खेती बाड़ी में हरियाणा के किसान किसी तरह भी पीछे नहीं रहेंगे। आज उन दोनों के चले जाने से हाउस को तथा हरियाणा सूबे को बहुत घाटा हुआ है। मुझे सुरेन्द्र सिंह के पिता

जी के साथ काम करने का मौका मिला। यहां पर चौधरी सुरेन्द्र हिंस की धर्मपत्नी बैठी हुई है और जिन्दल साहब की धर्मपत्नी भी बैठी हुए हैं। बहुत ही दुख है वे लोग जिनके सामने कुछ निगाना था वे आज हमें छोड़ कर चले गए। स्पीकर साहब, सुनील साहब, श्री सुनील दत्त जी को भी निधन हो गया है हमारे दोनों मन्त्रियों के साथ साथ जहाज के पायलट श्री चौहान जी भी चले गए हैं। इनके अलावा हमारे कई फ्रीडम फ़ाईटर भी हमें छोड़कर चले गए हैं। यह सारा हाउस उन परिवारों के प्रति हमदर्दी प्रकट करता है और परम पिता परमात्मा से उनके पीछे सुख और भांति मांगता है। मैं अपनी तरफ से और इस सदन की तरफ से यहाँ की भावनाएँ उनके भाग्य संतप्त परिवार के सदस्यों तक पहुँचा दूँगा। मैं सारे हाउस से यह निवेदन करूँगा कि दिवंगत आत्माओं की भांति के लिए दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय हाउस के सभी माननीय सदस्यगण ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया।)

सदस्य द्वारा भाषण/प्रतिज्ञान

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Madam Savitri Jindal, has come in the House. I call upon Smt. Savitri Jindal, a member who has returned in the Bye- election from 74 Hissar. Assembly Constituency of the Haryana Legislative Assembly held on 2nd June, 2005 to subscribe oath/affirmation of allegiance to the Constitution of India.

I will also request her for signing the Roll of Members placed on the Secreatry's table after making subscribe oath/affirmation of allegiance.

(At this stage- Smt. Savitri Jindal, subscribed oath/affirmation of allegiance to the Constitution of India.)

सदस्य प्रस्ताव की सूचना/वाक आउट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now Question Hour (Interruption) प्लीज आप भान्ति के साथ बैठे हम इतने भाोक मे बैठे हुए है, फिर भी बोले जा रहे है। कम से कम आप एक मिनट अब रूक तो जाओ। (गोर एवम व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Sir, I want to say scmething.

Mr. Speaker: Not at this stage.

Dr. Sushil Indora: Sir, I have given a notice of adjournment motion regarding retrenchement of more than 15000 Hayana Government employee. Particularly that of H.S.I.S.F. हम चाहते है कि प्रान काल से पहले इस बारे मे डिस्कान होनी चाहिए। (गोर)

Mr. Speaker: It does not lood nice. I am examining that. Please take your seat.

Dr. Sushil Indora: Mr. Speaker, यह 15000 इम्पलाईज के भविश्य की बात है।

Mr. Speaker: When I am saying that I examining that then why you ae interrupting. (Interruptionns) It is very sad you want to revert to last year. This is not the way. Nothing to be recorded. (Interruptions)

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, आप हमारे कास्टोडियन हैं और आप ही हमारी बात नहीं सुनेगे तो कैसे काम चलेगा। आप को इस बारे में प्रान्त काल से पहले डिसकान करवानी चाहिए।
(गौर एवम व्यवधान)

डा० सुशिल इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय,

इस समय इण्डियन नेशनल लोक दल के सदन में उपस्थित सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए।

Mr. Speaker: This is not the way. I will not allow.
(Interruptions) I have said categorically. I will not allow it.

डा० सुशिल इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय,

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय,.....

Mr. Speaker: I know what do you want. You want news in the New paper that you have staged walked out.
(Interruptions) Nothing to be recorded.

डा० सुशिल इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय,

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय,.....

Mr. Speaker: Nothing to be recorded. Let them say what they want to say (Interruptions) I will request you as a Speaker or as a friend to take your seat. This is not the time to speak. You have given the notice and I am examining that
(Interruptions) This is not the way.

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय,.....

Mr. Speaker: Please take your seat. I say, everybody has noted that you are fighting for them.

डा० सु गील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय,

Mr. Speaker: You have give the notice. I am considering it. (Interruptions) I will not allow it. Dalal Sahib, please go ahead.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, इन्दौर साहब सब कुछ जानते हैं। ये संसद के सदस्य भी रहे हैं और इस हाउस के भी माननीय सदस्य हैं। इन्होंने जो इस बारे में एक एडजर्नमेंट मोशन दिया है उसको आप कंसीडर कर रहे हैं। सात आठ दिन का हाउस है इसलिए इनको अपनी बात कहने का हर मौको पर पूरा समय मिलेगा। परन्तु आज तो कम से कम इनको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह समय क्वैचन आवर का है इसलिए क्वैचन आवर से पहले इनको हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। (गोर एवम व्यवधान)

डा० सु गील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय,

Mr. Speaker: Listen Mr. Indora. मुझे आपको एडजर्नमेंट मोशन आज डेढ़ बजे ही मिला है हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए अब आप बैठिए। (गोर एवम व्यवधान)
Please take your seat. This is what you wanted to do.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर सर, आज दे टर्मीनेटेड इम्पालाईज के हिमायती बनते हैं लेकिन इनकी सरकार के समय में 22 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

गया था परन्तु उस समय इन्दौरा साहब की आवाज एक बार भी नहीं निकली। (गोर एवम व्यवधान) स्पीकर सर, अगर इनका वाक आउट करने को लक्ष्य है तो अलग बात है। (गोर एवम व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे। दलाल साहब, सवाल करे। (गोर एवम व्यवधान)

डा सु गीला इन्दौरा: स्पीकर सर, अगर आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

इस समय इण्डियन नै नल लोक दल के सदन में उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गये।

ताराकित प्र न एवम उतर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now question Hour.

Amount realised on the auctioning of Liquor Vends

Shir Karna Singh Dalal: Will the Minister for Excise & Taxation be pleased to state-

(a) the total amount realised on the auctioning of Ilquor vends in the State for the year 2005-2006.

(b) the total amount realised on the auctioning of Ilquor vends in the State during the year 2002-2003,2003-2004 and 2004-2005; and

(c) whether there is any shortfall in the realization of revenue during the year 2002-2003,2003-2004 and 2004-2005 in comparison to the amount realised for the year 2005-2006 form the auction of Liquor vends; if so, the reasons thereof?

Excise & Taxation Minister (Sh. Vinod Kumar Sharma):

(a) the total amount of Rs. 837-99 crores has been realized on the auctioning of liquor vends in the State for the year 2005-2006.

(b) the total amount realised on the auctioning of Ilquor vends in the State during the year 2002-2003,2003-2004 and 2004-2005 in given as under.

Year	Amount (Rs. In Crore)
2002-2003	664.35
2003-2004	696.69
2004-2005	717.75

(c) the growth or shortfall in revenue can only be compared with the previous year. The percentage of growth of revenue in each of said years was as under:-

(figures in crores Rs.)

Year	Amount realized from the auction of liquor vends	Increase/decrease	%increase/decrease
2002-2003	664.35	34.23	5.43
2003-2004	696.69	32.34	4.87
2004-2005	717.75	21.06	3.02
2005-2006	837.99	120.24	16.75

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, मेरे सवाल का जो जवाब मंत्री जी ने दिया है वह सदन के पटल पर है मेरे सवाल

का पूरा जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है इसलिए मैं इनको फिर से रिमांड करवाना चाहता हूँ कि मैंने अपने प्रश्न में लास्ट में लिखा है कि if so, the reasons thereof अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उन्होंने जो जानकारी सदन को दी है उसके आधार पर मैं आपसे माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने निजी मुनाफा कमाने के लिए सारे कानून कायदों को ताक पर रख दिया था और एक्साइज एंड टैक्स इन विभाग की भी तमाम मर्यादाओं को तोड़ा था।

Mr. Speaker: Dalal Sabha. Put the Supplementary.
आप भाषण दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं यही पूछ रहा हूँ। इसमें जो उन्होंने इतना अंतर माना है तो ये इसके कारण बताएँ। मंत्री जी ने माना है कि वर्ष 2002-2003 में राजस्व की बढ़ौतरी की परसेंटेज 5.43 परसेंट, 2003-04 में 4.87 परसेंट और वर्ष 2004-05 में 3.02 परसेंट रही। अध्यक्ष महोदय, जब नई सरकार बनी और जब उसने इस बारे में एक साही तरीका अपनाया तो इस बढ़ौतरी में एक बहुत बड़ा अंतर आया है। इस सरकार ने प्रदेशों के लोगों को बहुत पैसा कमाकर दिया है।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, यह तो भाषण हो गया। Put the Supplementary.

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, भाषण में से ही कुछ न कुछ निकलेगा।

श्री अध्यक्ष: यह तो आप बाद में निकालते रहना। अभी बजट आना है। अभी आप केवल सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस इंक्रीज में जो इतना बड़ा अंतर है तो क्या मंत्री जी पिछली सरकार के इस विभाग के मंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ या इस विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ जो आकड़ों पर जाया करते थे, कोई जांच निष्पक्ष तरीके से करवाकर इस सदन को बताएंगे कि यह बड़ा घोटाला क्यों हुआ? क्या से उस वक्त मुख्यमंत्री, मंत्री या जो अधिकारी थे; के खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री विनोद कुमार भार्मा: Speaker Sir, Hon'ble Members has asked the question. He wants a clarification. I think my answer was quite explicit; still I would like to clarify the point that he has asked (Interruptions)

श्री आन्नद सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी हिन्दी में जवाब दें।

Mr. Speaker: Dalal Sabha, please take your seat. Minister is on his legs.

श्री आन्नद सिंह राठी: अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में सभी दस्यों को समझ में नहीं आता है।

Mr. Speaker: English is also the language of the House. If you want that all the Members should speak in Hindi then we will have to amend the rules.

श्री आन्नद सिंह राठी: यहा पर सभी सुनने के लिए बैठे है, सबको पता लगना चाहिए कार्यवाही का, कि सदन मे क्या कार्यवाही हो रही है। यहां पर दूसरे लोग भी बैठे है और सदस्य भी बैठे है।

श्री अध्यक्ष: डांगी साहब, आप बैठ जाइए।

श्री विनोद कुमार भार्मा: It is not necessary. Dangi Sahibi Sabhib, Please take your seat. I say, please take your seat.

Mr. Speaker: It is not necessary. Dangi Sahib, Please take your seat. I say, please take your seat.

श्री विनोद कुमार भार्मा: It is very clear from the table that the increase of revenue in the year 2002-2003, it was only 5.43% in the year 2003-2004 it was 4.87% in the year 2004-2005 it was 3.02% and in the year 2005-2006 this increase was 16.75%. Now, I can say that the increase in 2005-2006 is more than the 5 years cumulative increase put in together with. That means that the revenue collected previousy was less a compared to the revenue collected this year.

श्री बलवंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, आबकारी एमव कराधान मंत्री जी बडे ही काबिल वजीर है। इनकी भागुर मिले भी है, मै इनसे जानना चाहता हू कि यह जो इन्होने बताया है क्या यह बोली ओकसन का है। स्पीकर साहब, यह सही बात है कि वाकई मे इस साल रेवेन्यू बढा है। इसके अलावा मै जानना चाहूंगा कि जो भाराब का कोटा था क्या वह भी बढाया गया है? मेरे

कहने का मतलब है कि क्या भाराब का कोटा बढ़ाने की वजह से रेवेन्यू बढ़ा है? कृपया मंत्री जी इसकी जानकारी दे?

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, 1987 का कोटा पौलिसी के तहत ही बढ़ाया गया है। जो राशि 1 इन्क्रीज है वह जितनी रिफ्लैक्ट कर रही है वह हमने भाराब का जो कोटा बढ़ाया है उसकी अपेक्षा ज्यादा इन्क्रीज हुई है।

डा० सु गील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आबकारी एवम कराधान मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि सरकार के पास सारे आकड़े होते हैं और उन्हीं आकड़ों के आधार पर इन्होंने अभी जवाब सदन में दिया है। कृपया मंत्री जी बताएं कि वर्ष 1990-91 के आकड़े क्या थे और उस समय के क्या हालात थे?

Mr. Speaker: This is not relevant. आप मुझे यह कहते हैं कि दस साल पहले क्या हुआ। How we can say?

डा० सु गील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, फिर मेरी सप्लीमेंट्री का क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष: आपकी सप्लीमेंट्री तो काफी पुरानी है। आप 1990-91 की बात पूछ रहे हैं। If you want to ask the supplementary. तो आप अपनी सप्लीमेंट्री याद कर लो, फिर पूछ लेना। मैं आपको दोबारा दे दूंगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के

दौरान जितने ठेको की आवं उन हुई थी उनकी कीमत बहुत कम आंकी गई थी क्योंकि उसमें सबकी मिली भगत थी, उसमें सरकार की साजि ा थी, अधिकारियों का हिस्सा था और मुख्यमंत्री का हिस्सा था। अधिकारियों व मुख्यमंत्री की मिली भगत से जबरन ज्यादा बोली लगाने वालों को नीलामी की बोली नहीं लगाने दे जाती थी इसलिए कम रेवैन्यू आया। आज हरियाणा की जनता यह जानना चाहती है कि (विधन)

श्री अध्यक्ष: हां, यह कहो कि हरियाणा प्रदेश की जनता आज यह जानना चाहती है कि आप इसकी ऐलाबोरे ान न करो।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से फिर वही सवाल है कि पिछली सरकार के समय में पिछले वर्षों में जो भाराब से कम आमदनी हुई, उसके पीछे उस सरकार की साजि ा थी क्या मंत्री उसकी जांच कराएंगे या नहीं। इसके अतिरिक्त मैं मंत्री जी यह भी जानना चाहूंगा कि जब ठेको की आवं उन भुरू होती है तो मंत्री जी सदन को बताए कि जो अधिकारी आवं उन करने जाते हैं वे कौन से रूल के तहत और कौन से कानून के तहत जाते हैं। विभाग के अधिकारी 1/3 का नियम जब उनका मन आता है तब लगा देते हैं कृपया मंत्री जी सदन को यह भी जानकारी दें कि क्या इसके कोई रूलज और रैगुले ांज हैं? क्या इनकी वजह से सरकार को कोई फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है?

Sh. Venio Kumar Sharma: As per Rule 36 (12) of the Haryana Liquor Licence Rule, 1970 there is a condition of

depositing 1/3rd amount of the Bid at the time of auction to safeguard the revenue of Government and to discourage speculative bids. Everyone is free to bid after depositing 1/3rd of the money. This condition of 1/3rd is as per the rules and was intimated to all the prospective bidders before the auction and it was also incorporated as a part of the excise announcement. It is only to see when the bid is speculated to safeguard the revenue of the Government. It is not an additional amount asked from the contractor. It is within the amount has to be deposited but the amount is asked to ensure that he is capable of giving that much of money or may be after bidding. He may not leave the place and the Government cannot recover that money.

डा० सु गील इन्दौरा: स्पीकर साहब, पिछले साल साल 2004-05 में जो भाराब के ठेके दिए गये हैं वे कितने लाख प्रूफ लीटर थे और कितना कोटा निर्धारित किया गया था। साल 2005-06 में कितने लाख प्रूफ लीटर कोटा निर्धारित किया गया है और इसमें बढ़ोतरी कितने प्रतिशत हुई है?

श्री विनोद कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह इन्फोर्मेशन राईटिंग में भेज दी जायेगी।

प्र० छतरपाल सिंह: स्पीकर सर, माननीय मंत्री जी मैं यह जानना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में टोटल नम्बर आफ वैड्स कितनी है? कृपया मंत्री जी यह भी बताएँ कि अर्बन और रूरल के अलावा कौन कौन से जगह वैड्स स्थापित हैं?

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह इन्फोर्मेशन राईटिंग में भेज दी जायेगी।

प्रो० छतर सिंह: स्पीकर सर, इसी प्रश्न से संबंधित अगला प्रश्न यह है कि बड़ी भानदार इन्क्रीज भाराब के ठेके देने से हुई है। अगर यही वैडस इन्डिविजुअल तौर पर भांप के रूप में आवसन की जाती तो मैं समझता हूँ इसमें इम्पयामेंट जनरेटन ज्यादा होती और रेवेन्यू में भी ज्यादा इन्क्रीज होती। क्या सरकार भविष्य में ऐसी कोई योजना बनायेगी।

Shri Vinod Kumar Sharma: The vends are acutioned with the policy decision by the Government and the new policy for the year is to be decided by the end of March and nothing can be said about it.

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक सपलीमैट्री पूछना चाहते हूँ कि क्या पिछले भासन के दौरान जो ठेके नीलाम किए गये थे उनमें रेवेन्यू इतना कम था इस बारे में सरकार कोई इन्क्वायरी करवायेगी? क्या मंत्री जी इस प्रकार की इन्क्वायरी करवाने का आवासन देगे?

श्री विनोद कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इन बारे में अपनी रिक्वायत लिखित रूप में दे दें उस पर गौर किया जायेगा।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने जनता को वचन दिया था कि हर घर में रोजगार देगे, कृष्णान को दूर करेगे। (विधन)

Mr. Speaker: Please sit down, I would not allow you to deliver lecture.

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने जनता को वचन दिया था कि हर घर में रोजगार देंगे। मेरे इस हिसाब से इन्होंने 1600 ठेके भाराब के दिए हैं। पहले की सरकार के समय तो ये ठेके एक ही आदमी के पास होते थे या चौटाला साहब, के खुद या रि तेदारों के पास होते थे। अब ये 1600 ठेके दिए गए हैं। अगर ये ठेके अलग अलग आदमियों को दिए जाते तो काफी लोगों को रोजगार मिलता।

श्री अध्यक्ष: आपका सप्लीमेंट्री क्या है?

श्री राम कुमार गौतम: कम से कम आगे इस बात का ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष: यह कोई सुझाव नहीं है, आप बैठ जायें।

Imbalabce in distribution of canal water

Shir Dharma Singh Malik, Sh. Naresh Yadav & Shri Sita Ram: Will the Minister Irrigation be pleased to be state-

(a) the total quantum of canal water available in the State of Haryana as it stored on 31st March, 2005;

(b) whether there is any imbalance in the distribution of water for irrigation in different areas of the State; and

(c) if the reply to part (b) above is in affirmative, the steps propoasied to be taken by the State Government to remove this imbalance in distribution of water?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) 31.3.2005 को भाखडा, पोंग और रणजीत सागर बान्धो मे उपयोगी पानी का भण्डारण क्रम T: 0.84 एम0ए0एफ, 1.79 एम0ए0एफ0 और 0.69 एम0ए0एफ0 था। दिनांक 31.3.2005 को सतलुज, रावी या ब्यास के एकत्रित हुए पानी मे से हरियाणा का हिस्सा 0.65 एम0ए0एफ0 था। सतलुज का 0.21 एम0ए0एफ0 तथा रावी ब्यास का 0.44 एम0ए0एफ0 था। जबकि यमुना पर कोई भण्डारण नही है।

(ख) जी हां, श्रीमान जी।

(ग) उपलब्ध नहरी पानी के बटवारे की असमानता को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जा रहे है।

1. उपलब्ध जल की आपूर्ति के समान बटवारे को सुनिश्चित करने की ओर अधिक ध्यान देना।

2. उठान नहर प्रणाली की वितरण क्षमता मे सुधार करना।

3. भाखडा नहर प्रणाली एवम यमुना नहर प्रणाली मे एक अतिरिक्त लिंक नहर का निर्माण करना।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी को निष्पक्षता और फराखदिली के लिए उनका धन्यवाद करता हू कि उन्होंने कम से कम यह माना तो सही है कि पानी के बटवारे मे अनियमितताए हुई है। पिछले 40 साल के अर्से मे तो किसी ने यह माना नही कि पानी डिस्ट्रीब्यूशन मे कोई अनियमितताए है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

माध्यम से मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ और इसके साथ साथ इस सरकार को मुबारिकवाद देता हूँ कि जो बात चुनाव के निदो मे कही गई, जो बात हमारे घोशणा पत्र मे आई थी कि हम पानी का समान डिस्ट्रीब्यू इन करेगे, आज वे इस बात के उपर आए है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से हय सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूँ कि वह वे एग्जैक्ट कौन से एरियाज है कि जिनके साथ अन्याय हुआ है, क्या उन्होंने उन एरियाज को आईडेंटिफाई क्योकि क्वै चन तो काफी वैग और इम्बैलै है। इम्बैलेंस तो यह भी कहा जा सकता है कि जो लोग ज्यादा पानी ले रहे है उनके साथ भी इम्बैलेंस हुआ है मंत्री जी बताए कि एग्जैक्ट कौन से एरियाज है जिनके साथ ज्यादाती हुई है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि पानी के डिस्ट्रीब्यू इन मे डिसक्रिमीने इन है खासतौर से बी०एम०एल० जो सिस्टम है जिसमे सिरसा, फतेहबाद के एरियाज आते है। उस एरियाज मे जो अवेलबेल वाटर है उसमे 70 प्रति 100 पानी ज्यादा जा रहा है। स्टेट का जो आन एन एवरेज वाटर है वह 1856 एम०ए०एफ० है लेकिन यहा खरीफ सीजन मे 1987 एम०ए०एफ० वाटर जा रहा है। उसी प्रकार रबी मे जो हमारा आन एन एवरेज वाटर है वह 1281 एम०ए०एफ० है जो बी०एम०एल० सिस्ट है जिसका मैंने जिकर किया है, वहा 179 एम०ए०एफ० पानी जा रहा है और जिन एरियाज के साथ ज्यादाती हुई है वे खास तौर से लिफ्ट इरीगे इन सिस्टम के एरियाज है जो डब्ल्यू जे०सी० सिस्टम है वहां पर कुछ इस

प्रकार की ज्यादातियां हुई है कुल पानी आज के दिन लिफ्ट सिस्टम में प्वायंट 929 एम0ए0एफ0 जा रहा है। रबी के दौरान प्वायंट 849 एम0ए0एफ0 जा रहा है इसी प्रकार पहले बहुत भारी अनियमितताएं हुई थी। उनको देखते हुए हमने कोर्नर की है कि सिस्टम में कुछ सुधार लाए और इसके लिए हमने कई योजनाएं चलाई है सबसे पहली कार्यवाही हमने जो की है वह यह है कि जितने लिफ्ट कैनाल में पम्पस थे उनको दोबारा रिपेयर कराया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, मलिक जो सप्लीमेंटरी पूछी है कि किन किन एरियाज में पानी कम मिला है उन्होंने यह नहीं पूछा कि टोटल कितना प्रोड्यूस हुआ है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि भिवानी, रिवाड़ी, रोहतक, झज्जर के किसानों के साथ ज्यादाती हुई है और उनको कम पानी मिला है। ज्यादा पानी तो केवल डेढ जिले को ही मिल रहा था।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हू कि भिवानी जिले को पहले 3.5 क्यूसिक्स पानी मिलता था और अब उसको कम करके 2.5 क्यूसिक क्यों कर दिया गया है?

15.00 बजे

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी ने जो मुद्दा उठाया है इस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जिस समय यह लिफ्ट कैनल बनी थी उस समय यह विचार कि जो रेतीला एरियाज है जहाँ पर लिफ्ट कैनल के थ्रू पानी लिफ्ट किया जायेगा। वहाँ पर पानी को रेट 3.05 क्यूसिक पर थाउजैंड एकड होगा और बाकी के एरियाज में 2.4 क्यूसिक पर थाउजैंड एकड होगा। मेरे माननीय साथी ने यह सही बात कही है कि इस 3.05 क्यूसिक पानी को 2003 में पिछली सरकार ने जान बूझ कर कम करके उस एरिया के साथ भेदभाव करने के लिए 2.4 क्यूसिक कर दिया गया था। इस बारे में मैं मेरे साथी रणबीर सिंह जी को बताना चाहूँगा कि इसको रिव्यू करवाने के लिए हमने अपने विभागीय अधिकारियों को आदेश दे दिया है और पानी के मामले में पहले जो अनियमितताएँ होती रही थी, उसको हम दूर करेंगे।

चौ. धर्मपाल सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो पहला सप्लीमेंट्री था उसका जवाब मंत्री जी ने महेन्द्रगढ़ से भुरू करके रोहतक तक खत्म कर दिया और ये सोनीपत तक नहीं पहुँचे। जो एरियाज Identity करने थे पुराना रोहतक Including सोनीपत व पानीपत उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से एक एडयंत्र के तहत यह नारा लगाते रहे कि हमारे इलाके को एस0वाई0एल0 का पानी आने पर पूरी पानी मिलेगा। लेकिन एस0वाई0एल0 का पानी कब तक आयेगा इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आप देख रहे हैं कि 40 साल हो गये, अब तक जो पानी आया नहीं है। अब मेरा दूसरा

सप्लीमैट्री यह है कि आज के दिन हमारी स्टेट मे जो पानी मौजूद है क्या उसका बंटवारा बराबरी के आधार पर हमारी सरकार करेगी और करेगी तो कब तक यह इम्पीमेंट हो जायेगा। एस0वाई0एल0 का पानी जब आयेगा उसका बटवारा तक हो जायेगा लेकिन इस समय जो पानी मौजूद है उसका समान बंटवारा कब तक किया जायेगा और कौन से चैनल से यह पानी सोनीपत के एरिया मे आयेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मनानीय साथी ने जो बात की है यह बिल्कुल सही कही है। नरवाना ब्राच की कैपेसिटी 4202 क्यूसिक है, जिसका पानी साउथ हरियाणा मे जाता है जिसमे सोनीपत का एरिया भी आता है उसमे पानी की काफी दिक्कत रहती है इसमे कुछ पजांब का एरिया भी पडता है। इस समस्या को दूर करने के लिए एक तो हमने जिस नहरों की आज तक डीसिल्टिंग नही हुई। उनकी डीसिल्टिंग करवा रहे है जिस पर आने वाले 3-4 महीने मे 10 करोड रूपये खर्च करेगे, जिसमे जे0एल0एम0 भी भामिल है और दूसरी नहरे भी भामिल है। हम को ि । । कर रहे है कि जो नहरे नाले बन गई थी वे दोबारा से नहर बन सके। माननीय साथी ने पूछा कि साउथ हरियाणा मे किसी प्रकार पानी आयेगा? इस बारे मे मै बताना चाहूंगा कि एक और हम भाखडा का पानी लाने के लिए बी0एम0एल0 हांसी ब्रांच और बुटाना ब्रांच मल्टी परपज लिंक कैनाल बना रहे है और इस परियोजना के द्वारा तकरबीन 2000 क्यूसिक पानी आयेगा। पहले सिर्फ नरवाना ब्रांच से यह पानी आता था, अब इसके पैरलल दूसरी लिंक कैनाल बना रहे है जिस पर

करीबन 200 करोड रूपये खर्च होंगे। यह कनाल 106 किलो मीटर लम्बी होगी और इसकी कैपेसिटी 2000 क्यूसिक होगी। इस कनाल को बनाने के बाद जब बरसात के दिनों में कैथल और जीद के एरियाज में जो बाढ़ का पानी होगा वह पानी राईस ग्रोविंग एरियाज में दिया जायेगा। जहां तक साउथ हरियाणा की बात है, जिसमें सोनीपत का एरिया भी है वहां पर खासतौर से इसका पानी मिलेगा। जहां तक मौजूदा पानी के इम्बेल्मेंस का सवाल है उसको दूर करने के लिए और केवल 1.62 एम0ए0एफ0 रावी ब्यास का पानी जो हमें मिलना चाहिए उसके हिस्से की बात कर रहे हैं। जो पानी हमें एस0वाई0एल0 से मिलता है वह अलग ई पू है लेकिन इसके बनने से मैं समझता हूँ कि यह जो अनियमितता पानी की है इसको हम दूर कर पायेंगे और आज जो 16 दिन पानी आपकी नहर में चल रहा है उसको बढ़ाकर 24 दिन चला सकेंगे।

राव दान सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने एक बात स्वीकार की है कि पानी के वितरण में असमानता रह है। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूँगा कि दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र महेन्द्रगढ़ एवम रिवाड़ी आज तक पानी से अछूते रहे हैं। इन इलाकों के लिए सरकार पानी का प्रावधान कर रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार पानी का जो प्रावधान कर रही है हमें किस मात्रा में पानी मिल पाएगा और किस चैनल से मिलेगा, अगर यह ब्लॉक वार्डज स्थिति बताने की कृपा करें तो धन्यवाद होगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इन्हे नरवाना लिंक ब्रान्च के द्वारा पानी मिल रहा है। ज्यादा पानी देने के लिए हमारे जितने भी पम्प हाउसिज है उनको हम दोबारा से ठीक करवा रहे है क्योंकि पम्प हाउसिज की लिफ्टिंग कैपेसिटी मात्र 25-30 प्रति गत रह गई थी उसकी क्षमता को बढ़ाएगे। यह क्षमता बढ़ जाने के बाद मै यह समझता हू कि पहले जो पानी 7-8 दिन तक चलता था तथा 22-23 दिन बन्द रहता था हमारी सरकार आने के बाद अब हम 16 दिन तक पानी चला रहे है। 33 प्रति गत हमने आलरेडी इन्क्रीज कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, अब हम नहरो की डि सिल्टिंग का काम भी करवा रहे है और इस काम पर करीब 10 करोड रूपये खर्च होंगे। अगले 3-4 महीने मे जे0एल0एन0 कैनल की डि सिल्टिंग करवा देगे। जे0एल0एन0 कैनल जब से बनी है उसकी डिसिल्टिंग नही हुई है और जितने भी लिफ्ट कैनल है उनकी डि सिल्टिंग नही हुई है और न ही किसी कैनल की रिपेयर हुई थी। इस दि ग मे हम कदम उठा रहे है। यह जो हांसी और उकलाना ब्रान्च है उसके द्वारा कुछ पानी सोनीपत और झज्जर के ऐरिया मे चला जाएगा और यह जो ऐरिया लिंक ब्रान्च है उससे हमारे ऐरिया मे पानी आ जाएगा और पानी की मात्रा बढ़ जाने से हम 16 दिन की बजाए 24 दिन तक पानी चलाएगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा: अध्यक्ष महोदय, यह जो चर्चा हो रही है इसके बारे मे मै हाउस को बातना चाहूंगा कि सरकार की नीति है और किसानों के बारे मे भी प्रदे ग मे सभी संसधानो के समान बटवारे की बात थी। जिले और इलाके का कोई सवाल नही

है। सिंचाई के हमारे दो सिस्टम हैं एक है भाखडा सिस्टम और दूसरा यमुना सिस्टम है, इनसे सब को समान पानी मिलेगा। इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए वह एप्रोप्रियेट कदम सरकार उठा रही है ताकि टेलो तक पानी पहुंच सके। जो हमारा अवेलेबल वाटर है उसका समान बंटवारा होगा चाहे कोई भी इलाका है सारा हरियाणा एक समान है और सारे हरियाणा में सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी समुचित तरीके से और समान तरीके से सब को मिलेगा, यह हमारी नीति है और उसके लिए जो भी एप्रोप्रियेट स्टेप्स हैं वे हम उठा रहे हैं।

डा० सीता राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहता हूँ। पानी के बंटवारे के बारे में उन्होंने एक नगर बनाने का जिकर किया है। मैं उनसे यह जानकारी चाहता हूँ कि जहां से नहर भुरू होगी और जहां पर नहर खत्म होगी उसका स्लोप कितना है, क्या यह प्रोजेक्ट वहां तक पानी पहुंचाने में वायबल होगा और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगेगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरे में मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि अभी जो उपलब्ध पानी है उसके बंटवारे की बात सरकार करती है। क्या सरकार की यह मन्ता नहीं है कि एस०वाई०एल० नहर को जल्दी से जल्दी बनवा कर पानी का न्यायोचित बंटवारा किया जाए क्योंकि वास्तव में तो समस्या का हल उसी से होगा। मंत्री महोदय इसके बारे में बताने का कष्ट करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उतर दिया है वह स्टेट में पानी के वितरण में इस्बैलेंस हुआ है उसके

बारे में था। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि अभी बताया गया है कि कोई रीजन की बात नहीं है कोई इलाके की बात नहीं है सरकार पूरे हरियाणा में पानी के समान वितरण की बात कर रही है। पिछले 40 साल से 70 प्रतिशत फालतू पानी ये लोग ले रहे हैं जिसके कारण वहां पर सेम की समस्या हो रही है। दूसरी तरफ हमारे इलाके में पीने का पानी भी नहीं है। महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी के इलाके ऐसे हैं जहां पानी 1400 फुट तक नीचे चला गया है। अध्यक्ष महोदय, हम जो बात कर रहे हैं वह तो समानता की बात कर रहे हैं जब कि इन लोगों ने असमानता की बात की थी। जहां तक एस0वाई0एल0 की बात है, मामला अभी कोर्ट में लम्बित है और माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें जो भी आदेश देगी उसे हम मानेंगे।

श्रीमती अनीता यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से स्वीकार किया है कि दक्षिणी हरियाणा में 15 या 17 दिन पानी दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले 2000 से 2005 के बीच जो गवर्नमेंट थी, उस भासनकाल में हमारे हिस्से का पानी किन जिलों में ज्यादा जाता था?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं इस के बारे में पहले ही जवाब दे चुका हूँ।

Consturction of over Birdge on Bhiwani-Tosham Road

27. Dr. Shiv Shankar Bharwaj: Will the Chief Minister be pleased to be state whether there is any proposal

under consideration of the Governemnt to Consturct a Railway Over Bridge on the Bhiwan Tosham Road (Railway Crossing).?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): श्रीमान जी नही। स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय सदस्य ने ओवर ब्रिज बनाने के बारे में कहा है तो मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि सरकार का वहां पर अभी ओवर ब्रिज बनाने को कोई प्रपोजल नहीं है। स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को केवल यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1977 में इस प्रकार का ओवर ब्रिज बनाने के प्रपोजल बनाया गया था लेकिन वह प्रपोजल लागू नहीं हुआ था इसलिए हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड में बाय पास जो भिवानी और तो गाम रोड तथा भिवानी और लोहारू रोड है वह बनवा दिया था जो आपका ब्रिज था उसको डिफ्ट करके जो रेलवे लाईन क्रॉसिंग 51 सी जो कि भिवानी दू लोहारू रोड पर है उसको भिवानी दू भंटिडा रेलवे लाईन क्रॉस करती है। यह 1986-87 में बनकर तैयार हो गई थी। स्पीकर सर, कारण यह है कि अगर जो ओवर ब्रिज माननीय सदस्य बनाने के लिए कह रहा है अगर उसको बनाया जात है तो वहां पर जो अनाथ आश्रम है उसको सारे का सारा गिराना पड़ेगा और उसी जमीन लेनी पड़ेगी। इसी वजह से यह ओवर ब्रिज न बनाकर के बांया पास का निर्माण किया गया था और ओवर ब्रिज बनाने का प्रपोजल सरकार के पास विचाराधीन है।

डा० विंकर भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, यह जो ओवर ब्रिज डिफ्ट किया गया था, उससे वहां की समस्या का

समाधान नहीं हुआ है। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है। मैं आपके माध्यम एक लैटर पढकर सुनाना चाहता हूँ जो कि एस0सी0पी0डब्ल्यू0 ने इजिनियर इन चीफ को लिखा था और इसका सब्जैक्ट न0 318 / ROB in Bhiwani & Tosham Road. D.O. No. 36/CWEP, dated 13-10-2004, No. 3183/NH, dated 20-10-1994, इसमें भी एग्जिक्यूटिव इंजिनियर ने जो माना है उसकी वे दो लाईने मैं पढकर सुना देता हूँ।

श्री अध्यक्ष: भारद्वाज जी, आपके पास यह लैटर कहा से आ गया है। आप उसको क्यों मरवाना चाहते हो।

डा० शिवाजी कांर भारद्वाज: स्पीकर सर, उसको मरवाने की बात नहीं है यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है और मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए जरूर कुछ न कुछ करे क्योंकि 1/3 से ज्यादा पापुले उन वहां पर रहती है और लाईफ सेविंग टाइम उस फाटक पर लोगो को वेस्ट होता है। घंटो फाटक वहां बंद रहता है जिसकी वजह से कई बार गर्भवती महिलाओ की वही पर डिलवरी हो जाती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हार्ट अटैक वाले पे गान्ट फाटक बंद होने की वजह से अस्पताल में समय पर न पहुंचने की वजह से वही पर जान दे देते है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह ओवर ब्रिज बनाना बहुत ही जरूरी है और सरकार को इसको प्रायोरिटी बेस पर बनवाना चाहिए। सर, उस लैटर से जो दो लाईन्ज है मैं आपके माध्यम से सदन में पढकर सुनाना चाहता हूँ। The Executive Engineer, has further brought out, "is is fact that the Railway Crossing No. 53 on Tosham Bhiwani road remaing closed for long hours resulting in long ques of vehicles

awaiting the crossing of Railway Line.” सर, यह उन्होंने अपनी लैंटर में माना है कि यह बहुत ही गम्भीर समस्या है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूँ लेकिन सरकार के सामने दो रास्ते हैं। उसमें से एक रास्ता है जो अनाथ अबोध बच्चों का आश्रम है, यह सारे का सार गिरा दिया जाए और उनकी जमीन ले ली जाए। स्पीकर साहब, रेलवे अथोरिटी ने जो हमें रिपोर्ट दी है उसमें यह लिखा है कि अगर यह ओवर ब्रिज बनाया जाएगा तो उसके बीच में अनाथ आश्रम आएगा। सरकार ने इस बात को ही देखते हुए यह निर्णय लिया है कि यह जो आश्रम अबोध बच्चों का बहुत ही पुराना आश्रम है इसको रेलवे ब्रिज के लिए गिराना उचित नहीं है। स्पीकर सर, वहाँ पर बाँय पास की सुविधा है। 51 नम्बर क्रॉसिंग पर आल रेड्डी ओवर ब्रिज बना दिया गया है इसलिए यह सम्भव नहीं है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूँगा कि आल रेड्डी 90 करोड़ 56 लाख रूपए की लागत से कई रेलवे ओवर ब्रिज यहाँ पर बना रहे हैं और 130 करोड़ रूपए की लागत से कई ओवर ब्रिज बनने विचाराधीन हैं तथा इनके एस्टीमेट्स मंजूर हो चुके हैं। और पैसे की भी कोई कमी नहीं है। माननीय सदस्य जिस विषय में कह रहे हैं यह एक ऐसी मार्मिक समस्या थी इसलिए सरकार ने यह फैसला किया कि यहाँ पर ओवर ब्रिज ने बनाया जाए।

श्री एस०एस० सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि कैथल में नई अनाज मंडी के पास जो रोड जाती है, उस पर बहुत कंनै िन

रहती है क्या वहां पर कोई ओवर ब्रिज बनाने की सरकार की योजना है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ रूपए की लागत से नई अनाज मंडी के पास रेलवे ओवर ब्रिज की योजना सरकार के पास विचाराधीन है। इसकी प्रपोजल 13 दिसम्बर, 2002 को हमने सबमिट की थी। अध्यक्ष महोदय, रेलवे विभाग के पाय यह योजना पैण्डिंग है। सरकार का प्रयास रहेगा कि उनसे मजूरी लेकर इसको जल्दी भुरु करवाए।

प्रो० छतरपाल सिंह: स्पीकर साहब, जब हिसार से दिल्ली की तरफ निकलते है तो There is another Railway Phatak. There is heavy traffice on it. जिदल साहब की फैक्ट्री के पास यह एरिया पडता है। क्या उस एरिया मे भविश्य मे ओवर ब्रिज बनाने का कोई प्रपोजल सरकार के विचाराधीन है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि रेलवे ओवर ब्रिज नम्बर 89 बी जी है वह सात रोड हिसार की रेलवे लाईन पर है, उसके लिए हमने टैंडर कर दिया है और 30 जून, 2006 तक यह काम पूरा हो जाएगा।

श्री धर्मबीर गाबा: स्पीकर साहब, मैं आपमे माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हू कि ओवर ब्रिज बनाने का क्राइटेरिया क्या है? क्या अवेलेबिलिटी आफ फंड्ज अवेलेबिलिटी आफ लैंडज या ट्रैफिक इसका क्राइटेरिया है? सरकार का किस आधार पर ओवर ब्रिज बनाने का क्राइटेरिया है? जो मेन भाहर है

क्या वहां पर भी रेलवे ओवर ब्रिज बनाएंगे? जैसे गुडगांव में दौलतबाग रोड के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने की बात है तो क्या गुडगांव में वहां पर उस रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को बताऊँगा कि यह सब प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं यह सप्लीमेंट्री के स्कोप में तो नहीं आते हैं लेकिन इस बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवैलबल थी वह मैंने बता दी है। अगर माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर देंगे तो सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि गुडगांव की प्रगति सरकार की प्राथमिकता में है और हम उस ओवर ब्रिज को भी अवैलबल बनाएंगे।

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर साहब, मैं रेलवे विन्ट क्वेश्चन पर ही आपके माध्यम से अनारबल मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी भिवानी में रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की बात कही गयी थी। यह मान लिया कि वहां पर गरीब अनाथ बच्चों का आश्रम बीच में आता है। मैं मंत्री जी जानना चाहूँगा कि क्या सरकार वहां पर इसके आल्टरनेट के रूप में सब कुछ या अन्डर ब्रिज बनाकर लोगों की समस्या का हल करेगी ताकि वह आश्रम भी वहां कायम रहे और लोगों की जो बहुत बड़ी पीडा है उसका भी निवारण हो सके।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले दूसरे माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में बताया था कि वहां पर दोनों तरफ बिल्डिंग होने की वजह से ऊपर और नीचे की खुदाई करना संभव नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो वहां पर लोगों के मकानों और उस अनाथ आश्रम को भारी क्षति पहुंचगी। फिर भी माननीय सदस्य ने जो कहा है कि उसको हम टैक्नीकली ऐग्वान्टिन्स करवा लेंगे।

डा० सु गील इन्दौरा: स्पीकर साहब, केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार की सारी फार्मैलिटीज पूरी होने के बाद सिरसा और डबवाली में रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के लिए िलान्यास किये गये थे। मैं आपसे माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इनका काम कब शुरू होगा और कब तक यह पूरा हो जाएगा यानी इस बारे में जो स्थिति है उसको कृपा मंत्री जी जरा विस्तार से बताएं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने डबवाली में ओवर ब्रिज बनाने की चर्चा की और कहा कि यहां पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का िलान्यास किया गया था। सर, हमने एक मार्च, 2005 को इसके लिए मिनिस्ट्री आफ िपिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट को पैसा जमा करवाया है। यदि मेरे पास इस बारे में फिगर्स सही हैं तो इसका ऐस्टीमेट एक करोड़ रुपये के करीब है बाकी की जो तपसील ये जानना चाहते हैं उसके बारे में ये लिखकर भेज दें, मैं उसका जवाब दे दूंगा।

**Opening of Hundred Bed Government Hospital in Village
Bass**

23. Shri Ram Kumar Gautam: Will the Minister of Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open hundred bed Govt. Hospital in village Bass in Narnaund Constituency.?

स्वास्थ्य मंत्री (बहन करतार देवी): जी नहीं। स्पीकर साहब, इसके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि सरकार के बांस गांव में 100 बैडज होस्पिटल बनाने का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य केन्द्रों को बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनी हुई है। इस नीति के हिसाब से तीस हजार की आबादी पी०एच०सी० और एक लाख बीस हजार की आबादी पर पी०एच०सी० एवम इसके लिए आगे दूसरे होस्पिटल बनाये जाते हैं। स्पीकर साहब, वहां एक पी०एच०सी० काम कर रही है जिसके अंदर आठ सब सैटर्ज पडते हैं। जिनकी टोटल आबादी चालीस हजार के करीब है इसलिए इस पी०एच०सी० की तो इम्पुवमेंट हो सकती है लेकिन अलग से 100 बैडज का होस्पिटल बांस गांव में बनाने का कोई इरादा सरकार का नहीं है।

श्री राम कुमारा गौतम: स्पीकर सर, बांस गांव हरियाणा के दस बड़े गांवों में से एक है यह मेरी कास्टीच्यूएन्सी का भी सबसे बड़ा गांव है। आसपास के कम से कम 15 गांव ऐसे हैं जहां एम०बी०बी०एस० डाक्टर नहीं है। खुद बांस गांव में कोई एम०बी०बी०एस० डाक्टर नहीं है। लोगों ने मेहनत करके दस लाख, पन्द्रह लाख रुपये इकट्ठे किए हैं। वहां के लोग चौटाला साहब के पहले ज्यादा गीत गाते थे, उनके पास गए थे कि आप बनाओ चौटाला साहब ने वहां पर एक फोटो तो चौधरी देवी लाल की वहां लगा दी लेकिन काम अभी तक भुरू नहीं किया। मेरी

मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वहां बहुत ही सख्त जरूरत है इसलिए वहां सौ बैड का आसपास जरूर बनाया जाए।

बहन करतार देवी: अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बात चुकी है कि वहा पर आकर सब सैन्टर्स को मिलकार लगभग 42 हजार के करीब की ही आबादी बनती है इसलिए वहा पी0एच0सी0 का स्कोप है और वह आलरेडी वहां है यह बात अलग है कि वह प्राइवेट बिल्डिंग में चल रही है। पीछे एक बिल्डिंग बनी है वह साढ़े पांच फुट नीचे है इसलिए यह टेकओवर नहीं की है। स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं वे दूर नहीं हैं। यह मैंने बताया है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है कि वहां पर पी0एच0सी की नई बिल्डिंग बना दी जाए। जहां तक डाक्टरों का सवाल है उस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि इस समय सारे हरियाणा के लिए करीब 160 डाक्टरों की वहा कमी है लेकिन फिर भी वहां की जरूरत को देखते हुए एक डाक्टर और दूसरा स्टाफ वहां पर है और भी जल्दी से जल्दी वहा स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे और लोगों को सुविधाएं मिलें इसका पूरा प्रबंध किया जाएगा लेकिन 100 बैड्स अस्पताल बनाने का कोई विचार नहीं है।

श्री खरैती लाल भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपमें माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन्होंने बताया कि 40 हजार या 42 हजार की आबादी पर पी0एच0सी0 बनाई जाती है। मेरे हल्के में ठोल गांव है, उसकी और उसके आसपास की आबादी 42 हजार से ज्यादा बनती है। वहां गांव वालों ने पी0एच0सी0 के लिए बिल्डिंग बनाकर दी है और बहुत रिक्वेस्ट की

है कि उसको सरकार टेक ओवर कर ले और वहां पर डाक्टरों का इंतजाम किया जाए। मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार क्या कोई ऐसा प्रावधान करेगी कि वहां पर डाक्टरों और दवाइयों की इंतजाम हो सके।

बहन करतार देवी: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सप्लीमेंट्री इस मेन सवाल में कवर नहीं होती। वहां पर डाक्टरों भेजे जाने के लिए माननीय सदस्य द्वारा और वहां के लोगों द्वारा भी लिखकर दिया गया। इसको हम ऐगजामिन करा रहे हैं यदि बिल्डिंग नामर्स के हिसाब से सही हुई और नई जनगणना के हिसाब से सरकार ने जो नयी पी0एच0सी0 बनानी है, उसमें हम टोल को शामिल कर सकते हैं।

प्रो० छतरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि हरियाणा में चाहे पी0जी0आई0 रोहतक है और चाहे दूसरे जिलों के जो अस्पताल हैं उनमें स्टाफ का जो रिक्वायर्ड वर्कलोड है। क्या वह पूरा है और यदि नहीं है तो कब तक पूरा कर देंगे। इसके अलावा यदि किसी अस्पताल में स्टाफ है तो इक्विपमेंट्स नहीं हैं और इक्विपमेंट्स हैं तो स्टाफ नहीं है। Equipments are not functioning due to the shortage of the staff. क्या मंत्री महोदया के पास पूरे स्टाफ का विवरण है अध्यक्ष महोदय के साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या स्टाफ की और इक्विपमेंट्स की पोस्टिंग को बैलेंस करने का निकट भविष्य के कोई विचार है।

बहन करतार देवी: स्पीकर साहब, वैसे तो इक्विपमेंट्स विवरण मेरे पास नहीं है। लेकिन यह सही है कि हम अब की बार स्थानान्तरण जो करेंगे उसमें स्पैशियलिटी के हिसाब से सी0एच0सी0 लैवल पर दो डाक्टरों को पोस्ट करेंगे। आपरे एन थियेटर होगा वहां सर्जन को पोस्ट करेंगे और जहां एक्सरे मॉनिंग होगी वहां रेडियोग्राफर की पोस्टिंग करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो सुविधा जहां होगी उसके मुताबिक स्टाफ भी होगा। यह मैं पहले ही स्वीकार कर चुकी हूँ कि डाक्टरों और पैरामेडीकल स्टाफ की कमी है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि इस कमी को आने वाले 2-4 महीनों में पूरा करेंगे।

श्री एस0एस0 सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, कैथल डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है और वहां पर दूर दूर तक कोई मेडीकल फ़ैसिलिटीज नहीं है। वर्तमान में कैथल अस्पताल की जो बिल्डिंग है वह काफी पुरानी है और खराब कंडीशन में है। मैं मंत्री महोदय, से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई तजवीज कैथल में नये अस्पताल की माडर्न बिल्डिंग बनाने की है। हुडडा ने सैक्टर 18 कैथल में 15 एकड़ जमीन इसके लिए रिजर्व कर दी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कैथल और उसके आस पास के पूरे इलाके का ख्याल रखते हुए क्या वहां पर कोई सुपर स्पैशियलिटी अस्पताल बनाने का सरकार का कोई विचार है?

बहन करतार देवी: स्पीकर साहब, कैथल में इस समय 100 बेड का होस्पिटल है। यह ठीक है कि उस अस्पताल की बिल्डिंग खराब अवस्था में है। इस बारे में माननीय सदस्य के

साथ हम बैठकर मीटिंग कर चुके हैं। नये बजट में नई बिल्डिंग बनाने का प्रावधान किया गया है। यहां पर ही नहीं और भी डिस्ट्रिक्ट है हैडक्वार्टर पर अस्पतालों की नई बिल्डिंग बनाने का विचार है। रेवाड़ी और झज्जर जिला हैडक्वार्टर पर भी 100 बैड का अस्पताल बनाने का नये बजट में प्रावधान करेंगे।

श्री सोमवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1999 में मेरे हल्के के गांव ढिगावा में पी०एच०सी० बनाने का प्रोजेक्ट हैल्थ विभाग की तरफ से दिया गया था कि अगर पंचायत पी०एच०सी० के लिए जमीन दे दे तो वहां पर पी०एच०सी० खोल दी जायेगी। पंचायत ने इस बारे में रेजोल्यूशन पास करके जमीन भी दे दी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या वहां पर पी०एच०सी० खोलने पर सरकार कोई विचार करेगी?

बहन करतार देवी: स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि नये बजट में 200 के करीब पी०एच०सी० खोलने पर सरकार विचार कर रही है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को विवास दिलाना चाहता हूँ कि अगर जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम ट्रांसफर हो चुकी है तो नये नार्मस के हिसाब से हम वहां पर पी०एच०सी० खोलने के मामले को कंसीडर लेंगे।

श्री राधे भयाम भार्मा अमर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 500 घरों की बस्ती में जहां एक हजार या दो हजार लोग रहते हैं यहां पर उनको 25 किलोमीटर तक कोई मैडिकल सुविधा प्राप्त नहीं है।

क्या मंत्री महोदय उनके लिए कोई मैडिकल सुविधा देने बारे विचार करेगी ?

बहन करतार देवी: स्पीकर साहब, अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रूरल हैल्थ मिशन के नाम से एक नई योजना भुरु की है। उस योजना में हमारा स्टेट तो नहीं आता लेकिन फिर भी हम इस भावना को देखते हुए हम नई योजना भुरु करने जा रहे हैं इस नई योजना के तहत मोबाईल हैल्थ यूनिट बनाई जायेगी। जिसके तहत ऐसे गांव के लोगो को स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी।

श्री सुखबीर सिंह (सोहना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हू कि गुडगांव डिस्ट्रिक्ट जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा रैवेन्यू देता है क्या उसके बारे में भी सरकार द्वारा कुछ सोचा जा रहा है।

बहन करतार देवी: स्पीकर साहब, गुडगांव में इस समय 120 बेड का अस्पताल है। माण्डी में 50 बेड का, सोहना में 30 बेड का, और हेली मण्डी में 25 बेड का अस्पताल है। इस समय पूरे हरियाणा की जानकारी तो मैं नहीं दे सकता। माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर दे दे इनको जवाब दे दिया जायेगा।

Opening of a College at Bhondst Damdama

46. Shri Sukhbir Singh (Shohana): Will the Minister Education be pleased to be state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a college at Bhondsi Damdama and Badshapur being no college in that area ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized.?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना): नहीं श्रीमान जी।

श्री सुखबीर सिंह (सोहना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि भौडसी गांव की 100 एकड़ लैंड बी०एस०एफ० को, 450 एकड़ लैंड हरियाणा पुलिस को, 90 एकड़ लैंड जेल के लिए और 406 एकड़ लैंड सी०आर०पी०एफ० को सरकार ने एक्वायर करके दे रखी है। भौडसी और बाद शापुर दोनों गांवों की वोटर संख्या 10-10 हजार की करीब है और टोटल जनसंख्या 30 हजार के करीब है। इन गांवों की इतनी ज्यादा जमीन एक्वायर की हुई है लेकिन आस पास के गांवों में कोई सरकारी कालेज नहीं है इस लिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वहां सरकार कालेज खोला जाए।

श्री फूलचन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपमें माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि भौडसी, दमदमा और बाद शाहपुर तीनों ही गुडगांव जिले के भाग हैं। गुडगांव जिले में 10 कालेजिज है जिसमें 7 सरकारी, 2 गैर सरकारी और एक निजी महाविद्यालय है। भौडसी जहां का माननीय साथी ने जिकर किया है गुडगांव जिले के बिल्कुल साथ लगता है इसलिए 10 कालेजिज में से किसी भी कालेज में एडमिशन लिया जा सकता है। जहां तक इन्होंने जिकर किया कि जमीन किसी और काम के लिए ली

गई है तो उसका कालेंज मे कोई सम्बन्ध नहीं है, कालेज मे बहुत सी सुविधाए है। हमारी सरकार आज के युग मे शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रही है। साथ ही यह सरकार शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ज्यादा ध्यान दे रही है। जिसके तहत जांब ओरिएटिड कोर्सिज ज्यादा भुरू करने जा रही है। इसलिए अगर माननीय साथी को किसी भी कालेज मे एडमिशन मे दिक्कत आए तो मुझे बता दे।

Leasing of Mines Minister

19. Shri Naresh Yadav: Will the Chief Minister be pleased to be state whether there is any proposal under consideration of the Government to lease out the mines minerals of district Mahendergarh to the societies of the unemployed youth of the said area?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):नहीं, श्रीमान जी।

श्री नरेण यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है जब कि जवाब तो मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से जानना चाहता था लेकिन वे यहां मौजूद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हू कि पिछली बार हाउस मे बड़े जोर भाोर से आवाज उठी थी कि खनिज हरियाणा मे एक ही आदमी के पास है और आज भी उन्ही लोगो के पास है। खनिज पर, पहाडो पर, रेत पर और बजरी पर वे बैरियर, टोल टैक्स लगा कर बैठे है और जनता को परेशान कर रहे है। हम लोग सोचते थे कि नई सरकार बनेगी तो कुछ सुधार होगा लेकिन हमने देखा कि बजरी, रोडी आदि के दाम

बढते ही जा रहे है और उनके होसंले बुलंद होते जा रहे है।
हमारा जिला भुरवीरो का जिला है।

Mr. Speaker: Naresh Yadav Ji, please put the supplementary. Don't deliver the speech. You will get enough time for the speech.

श्री नरे । यादव: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हू कि जिनते खनिज हमारे जिले मे है, हमारे साउथ हरियाणा मे जिनते पहाड है, जितनी नदिया है जहां से बजरी और पत्थर निकलता है, उसके लिए बेरोजगार युवको की कमेटी बनाकर उनको ठेके दिये जाए न कि सेठ साहुकारो को दिये जाए जैसा कि पिछली सरकार मे दिया जाता था।

Mr. Speaker: Naresh Yadav Ji, you are suggesting the things. Please put the question. This is not the way. Don't deliver the speech.

श्री नरे । यादव: अध्यक्ष महोदय, मै यह पूछना चाहता हू कि क्या नई सरकार ऐसा कोई प्रावधान कर रही है कि जिसके तहत हमारे इलाके के जितने पहाड, नदिया या खाने है उनके ठेके हमारे इलाके के बेरोजगार युवको को ही मिले। हमारे इलाके के एरियाज मे अभी तक नहरी पानी भी पूरा नही पहुंचा है जिसकी वजह से वहां पर काफी लोग बेरोजगार है।

Mr. Speaker: Naresh Yadav Ji, you are delivering the speech. Please put the supplementary.

श्री नरे । यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमैटरी यही है कि क्या सरकार हमारे इलाके के पहाडो, नदियों, और खानो के ठेके हमारे इलाके के बेरोजगार युवको को देने का कोई प्रावधान करने जा रही है या नहीं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हू कि हरियाणा में 2 तरह के मिनलर्ज है एक मेजर मिनलर्ज और दूसरे माइनर मिनलर्ज। मेजर मिनलर्ज हमारे यहां दो प्रकार है एक सिलिका सैण्ड और दूसरे स्कूल स्लैट। इनकी इस समय 2 माईन्ज चल रही है बाकी सारी माईन्ज सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बन्द कर दी गई है। 2 माईन्ज एक फरीदाबाद में है और एक महेन्द्रगढ़ में है। माईन्ज आफ मिनलर्ज एक्ट जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है उसके अन्दर इनको देने की प्रक्रिया है। इस एक्ट के तहत प्रोसपैक्टिंग का लाइसेंस लेना पड़ता है और जिसको प्रोसपैक्टिंग का लाइसेंस मिलेगा अगर उसको वहां मेजर मिनलर्ज मिल जाएगा तो फिर उसको उस खनिज पदार्थ की माइन को लेने का प्रफेरेन्सियल राइट हो जाता है। अगर कोई भी सोसायटी चाहे वे बेरोजगार युवको को हो या फिर कोई दूसरी हो वह इस प्रकार के लाइसेंस के लिए भारत सरकार को एप्लाइ करेगी तो मुझे विश्वास है कि वे भारत सरकार अब यही इस पर विचार करेगी। जहां तक माइनर मिनलर्ज के बोर में हमारे सदस्य ने चर्चा की है उसके लिए हमारी सरकार ने स्पष्ट नीति बनाई है और वह नीति है साल दर साल आंकड़ों की। इस सरकार के बनने के बाद मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि केवल दो

माईन्ज समय पूरा होने के बाद आंकान के लिए आई थी। एक का समय दस महीन का है और दूसरी का समय 2.5.2005 से 31.3.2008 तक है तकरीबन तीन साल के लिए हैं। पंचकुला की पिछली सरकार के समय मे जो आंकान 9.50 करोड रूपये की हुई थी वही अब उसकी आंकान 35 करोड 41 लाख 6 हजार रूपये मे की है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते है कि कितनी अधिक बढोतरी हमारी सरकार ने की है। दूसरी माईन स्टोन क्यूरी फरीदाबाद थी जिसकी आंकान पिछली सरकार के समय मे 2.50 करोड रूपये की गई थी और हअब हमने उसकी आंकान 5.50 करोड रूपये मे की है। अध्यक्ष महोदय, मै पूरे सदन को आ वस्त करना चाहूंगा कि यह राजस्व से जुडा हुआ मामला है और हमारी सरकार ने माईन्ज पब्लिक आंकान मे देने का फैसला किया है। आप यह वि वास रखिये कि जो माईन्ज है वे आंकान के द्वारा पूरे पारदर्शी तरीके से दी जायेगी। मै सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि चाहे सोसायटी हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो हर व्यक्ति बोली लगाकर माईन्ज लेने के लिए स्वतंत्र है।

श्री नरे ा यादव: अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हू कि पिछली सरकार के समय मे कुछ लोगो को निजी फायदा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से माईन्ज लीज पर दी गई थी। इस बारे मे पहले भी काफी बहस हुई है। क्या मौजूदा सरकार पिछली सरकार के समय मे जो गलत तरीके से लीज दी गई है उन पर पुनर्विचार करके उनकी इन्क्वायरी करवाने के बाद उन लीजो का आवंटन ठीक ढंग से करायेगी या

नहीं इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि वहां जो नायायज टैक्स लिया जाता था क्या उसको रोका जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी को मैं गार भायद उस वि. ेश प्रकार के टैक्स की तरफ है जो पिछली सरकार के समय में भिवानी जिले और दूसरे क्षेत्रों में वसूला जाता था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माध्यम से माननीय साथी और पूरे सदन को बताना चाहता हू कि इस सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट और स्टिक निर्णय लिया है कि किसी प्रकार का गलत टैक्स अब हरियाणा में वसूला नहीं जायेगा। इसके साथ साथ मैं पूरे सदन को आ वास्त कराना चाहता हू कि जिस किसी वि. ेश माईन की ि. कायत तथ्यों के साथ कोई भी साथी देगा जो गलत तरीके से दी गई हो उसको जांच कराई जायेगी और दोशियों को सजा दी जायेगी।
(गोर एवम व्यवधान)

श्री राधे याम भार्मा अमर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हू कि माईन्ज से जो लोग बजरी निकालते हैं वे बजरी के साथ साथ पेड़ों को भी काटते हैं। क्या उन लोगों को पेड़ काटने की इजाजत सरकार की तरफ से दी हुई है? यदि नहीं दी गई तो क्या उन लोगों को पेड़ काटने से रोक जायेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि पेड़ों को काटने की इजाजत किसी व्यक्ति को नहीं है। जहां कहीं भी ऐसा हो रहा

है अगर उसके बारे में कोई भी साथी तथ्यों के साथ विचारकृत करेगा तो उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तरांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Compute Education

57. Shri Sher Singh: Will the Minister for Education be pleased to be state whether the Government is formulating any scheme to impart computer education on its own expenditure or charging the minimum fee so that the poor students could also benefit therefrom?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना): इस समय कुछ राजकीय महाविधालयों में बी०एस०सी० तथा बी०काम० स्तरपर ऐच्छक विषय के रूप में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुलक नहीं लिया जाता है। कुछ राजकीय महाविधालयों में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी छात्रों को पूर्णतः ऐच्छक आधार पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके लिए सेवा प्रदाताओं को भुलक अदा किया जाता है।

राजकीय महाविधालयों में भी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है जहां छात्रों द्वारा सेवा प्रदाताओं को निर्धारित भुलक की अदायगी की जाती है वर्तमान वर्ष 2005-06 के लिये सरकार लगभग 100 विधालयों में कम्प्यूटर

िाक्षा प्रदान करने के लिये एक स्कीम तैयार कर रही है जहां छात्रो से कोई अतिरिक्त भुल्क/प्रभार वसूल नही किया जायेगा। यह स्कील लागू करने से पहले भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

घोशणाए

Reduction in Yield of Wheat

2. Shir Karan Singh Dalal: Will the Chief Minister be pleased to be state-

(a) whether any reduction/decline in the per acre yield of wheat in the State been reported during Rs. 2004-2005 due to adverse weather condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the state Governement to provide compensation to the farmers in the loss in the yield of wheat?

मुख्यमंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) हा, महोदय।

(ख) रबी 2004-2005 के दौरान ओला वृष्टि के कारण हुई हानि का मुआवजा पहले ही अदा किया जा चुका है।

Anaj Mandi in the State

8. Shri Dharma Pal singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to be state-

(a) the total number of Anaj Mandi in the State registered with the Hayana State Agricultural Marketing Board as for Rabi Crops 2005; and

(b) the number of Anaj Mandi out of those referred to in part (a) above, do not have the proper facilities of sheds, flooring, drinking water and lighting, togetherwith the steps proposed to be taken to improve these Anaj Mandi.?

मुख्यमंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 105 मुख्य वार्ड व 70 उप वार्ड अधिसूचित है तथा 173 खरीद केन्द्र रबी फसल 2005 में खोले गए।

(ख) रबी 2005 में सभी मंडियों में पीने का पानी तथा रोशनी लाईट की सुविधा उपलब्ध है। ये सुविधाएँ खरीद केन्द्रों में रबी 2005 में भी प्रदान की गई है।

भौंडो व फरियाली की सुविधा क्रम क्र. 78 व 4 अनाज मंडियों में उपलब्ध नहीं है। इन सुविधाओं को कृषि उपज की मंडियों में आवक और भूमि फण्ड्स की उपलब्धता के आधार पर प्रदान करने के लिए चरणबद्ध पग उठाए जा रहे हैं।

Drainage System in Bhiwani City

28. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj: Will the Minister for Transport be pleased to be state-

(a) whether the Government is aware of the fact that the drainage system of Bhiwani City is improper because of which many colonies sub merge even due to slight rain; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to improve the drainage system of the aforesaid city?

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला):

(क) श्रीमान जी, उचित निकास प्रणाली भिवानी भाहर के केवल 25 प्रति ात क्षेत्र से प्रदान की गई है, परिणाम स्वरूप वर्षा के समय निचाई मे स्थिति क्षेत्रो मे कुछ सयम के लिस पानी भर जाता है ।

(ख) रबी 2004-2005 , मे भाहर के निचाई मे स्थित क्षेत्रो से निकास प्रणाली की बढौतरी हेतु 15500 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई जिसके अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है ।

Opening of Treasury of Narnanud

24. Shri Ram Kumar Gautam: Will the Minister for Finance be pleased to be state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Treasury City; District Hisar?

वित मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): नारनौंद जिला हिसार मे पहले से ही दिनांक 13.1.1997 से उप खजानो कार्य कर रहा है ।

Opening of Sainik School and Recruitment officers at Gurgaon

47. Shri Sukhbir Singh Sohand : Will the Chief Minister be pleased to be state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government ot reopen the Sainik recruitment officer in Gurgaon closed down in the year 1996; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Sainik School at Gurgaon?

मुख्यमंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) नहीं श्रीमान जी।

Setting up of University; Mohindergarh

20. Shri Narsh Yadav: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a University in district Mohindergarh?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना): नहीं श्रीमान जी।

Reclassification of Cities

58. Shri Sher Singh: Will the Chief Minister be pleased to be state-

(a) whether it is fact that Central Government has reclassified the cities on the basis of the census of 2001; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to reclassify the cities of the State on the census of 2001, togetherwith the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize?

मुख्यमंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) हा, महोदय।

(ख) नहीं। राज्य सरकार भाहरो का वर्गीकरण करने बारे केन्द्रीय पद्धति का अनुकरण नहीं करती।

अतारांकित प्रश्न एवम उत्तर

Construction of Roads in District Sonapat

1. Shri Dharam Pal Singh Malik: Will the Chief Minister be pleased to be state-

(a) the name of the roads in Sonapat District which have been metalled during the year 2004; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Governement to construct metalled roads in the aforesaid district during the year 2005-2006; if so, the details there of ?

मुख्यमंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) जिला सोनीपत मे वर्ष 2004-2005 के दौरान निम्नलिखित सडको को पक्का किया गया है:-

(i) लोक निर्माण भवन व सडक भाखा द्वारा

1. रिदान से धडवाल
2. भाबड से मेहराडा
3. माहरा से रभडा
4. राठधना से लिवान

(ii) हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा

1. खेडी मनाजाट से मुनीरपुर
2. मेहदीपुर से बख्तावरपुर
3. मुरथल से मुकीमपुर
4. जगदी ापुर से जठेडी
5. राठधना से बहालगढ सडक
6. खेबडा से ओरगांबाद
7. जुआं से भाम ानघाट
8. जाती से खुर्द से ताजपुर
9. भाहपुर तगा से सनपेडा
10. तेवडी से सदढाना
11. बलकुतबपुर से पुगथाला
12. हसनपुर से धतुरी
13. नयाबांस से सरदाना
14. कुराड इबराहिमपुर से भुगरमिल
15. हसनपुर से धतुरी
16. खुबडु से भावर
17. बडी से पिपली खेडा

18. सरगथल रेस्टहाउस
19. विलविलान स्कूल से गोहाना खरखौदा सडक
20. आबंली से रिठाल
21. हुडा वाला से सरफाबाद
22. छतौरा से मातण्ड

(ख) जिला सोनीपत मे वर्ष 2005-06 के दौरान निम्नलिखित सडको को पक्का करने का प्रस्ताव है।

(i) लोक निर्माण भवन व सडक भाखा द्वारा

1. नाहरी से मल्लाह माजरा

(ii) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा

1. सिलाना से चौलका
2. सफियाबाद से नाहरी
3. राठधना से बहालगढ
4. जैनपुर से बख्तावरपुर
5. जाती खुर्द से दिपालपुर
6. खेवडा से दिपलपुर
7. गुमड से गदी झजारा
8. लडसौली से राजपुर

9. खरखौदां सडक से बरौटा बस अडडा
10. हुडावाला से सरफाबाद
11. मिरजापुर से खेडी से सांधी
12. कथुरा से छिछराना

Opening of Voctional Institure at Village Fetehpur Biloch

2. Miss Sharda Rathore : Will the Chief Minister be pleased to be state-

(a) whether it is fact sanction for the opeing of Vocational Institute at Village Fethepur Biloch in Bllabgarh Consituency has been accorded by the Government; if so, the present position thereof; and

(b) if the reply to part (a) above be in negative whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Vocational Instituate in the aforesaid village?

िाक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द):

(ए) गांव फतेहपुर बिलोच मे व्यावसायिक िाक्षा संस्थान खोलने के लिए सरकार के किसी प्रकार की कोई स्वीकृति प्राप्त नही हुई है ।

(बी) गांव फतेहपुर बिलोच मे व्यावसायिक िाक्षा संस्थान खोलने के लिए सरकार के पास कोई मामला विचारधीन नही है ।

Taking Over the Control of Agra Canal

3. Miss Sharda Rathore: Will the Minister for Irrigation be pleased to be state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to take over the control of the Head works of Agra Canal; and

(b) if the reply to part (a) above be in negative whether there is any proposal under consideration a separate channel from Okhala head Works alongwith Agra Canal to take up the share of water of Haryana State?

मुख्यमंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) जी नहीं, महोदय।

(ख) जी नहीं, महोदय।

Construction of Sports Complex

4. Miss Sharda Rathore: Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether it is fact that the section for the construction of sports complex in village Ucha in Ballabgarh Contituency; has been accorded by the Government; if so, details thereof?

मुख्यमंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): नहीं, महोदय।

Number of Unapproved Colonies

3. Miss Sharda Rathore: Will the Minister for Industries be pleased to be state-

(a) the number of un approved colonies developed in the surrounding of Ballabgarh deuring last ten years;

(b) the number of colonies out of those referred to in part (a) above the control of the Head works of Agra Canal; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to approve the remaining unapproved colonies;

(d) whether it is a fact that some colonies referred to in part (a) above have been approved partially; if so, the names thereof along with the reason of partial approval of such colonies; and

(e) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide civic amenities to the newly approved colonies

उद्योग मंत्री (श्री लक्ष्मण दास अरोडा): श्री मान जी ।

(क) 1996 से बल्लभगढ़ के चारों और 22 अनधिकृत कालोनियों विकसित हुई हैं ।

(ख) ऊपर भाग (क) में सन्दर्भित 22 कालोनियों में से किसी भी कालोनी को स्वीकृत नहीं किया गया ।

(ग) इस समय सरकार के पास इन कालोनियों को स्वीकृत करने बारे कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) बल्लभगढ़ के चारों और विकसित अधिकतर अनधिकृत कालोनियों पहले से ही स्वीकृत कालोनियों का विस्तार हैं । 1994 तथा 1995 में स्वीकृत की गई 21 कालोनियों के नाम

संलग्न सूचि मे दिये गये है। स्वीकृति जो विस्तार हुआ है, वे अनाधिकृत कालोनियां है।

(ड) सरकार की वर्तमान नीति अनुसार स्वीकृत कालोनियों मे नागरिक सुविधाये उपलब्ध कराई जाती है।

30.6.1994 को नियमित की गई कालोनियाः—

1. चावला कालोनी, एक्सटेन्शन
2. लक्ष्मण कालोनी
3. शिव कालोनी एक्सटेन्शन
4. अजी कालोनी
5. फ्रेण्डज कालोनी
6. राजा नाहर सिंह कालोनी
7. विजय नगर
8. बिल्लू सैनीनगर
10. आर्य नगर
11. भाटिया कालोनी एक्सटेन्शन
12. यादव कालोनी
13. दौलत कालोनी

21.12.1995 नियमित की गई कालोनियाः—

1. कुन्दन कालोनी
2. राव कालोनी एक्सटेन्शन
3. भूदत कालोनी
4. भियम कालोनी
5. नाबलू कालोनी
6. संजय कालोनी
7. भगत सिंह कालोनी
8. भर्ग कालोनी एक्सटेन्शन

घोशणाए

(क) अध्यक्ष द्वारा

(i) चेयरपर्सन्ज के नामो की सूची

Mr. Speaker:: Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, the Hon'ble Speaker nominated the following members to serve on the Panel of Chairpersons:-

1. Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A
2. Shri Anand Singh Dangi, M.L.A
3. Shri Balbir Pal Shah, M.L.A
4. Shri Balwant Singh Sadhaura M.L.A

(ii) सदस्यो द्वारा त्याग पत्र

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am to inform the House that under Rule 58(2) of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Haryana legislative Assembly that Shri kishan Hooda, MLA has resigned from his seat in the Haryana Legilative Assemble No. 29 Kilo Assembly Constituency his letter dated 5th April, 2005 which was accepted by me form the said date.

(iii) अनुपस्थित की सूचना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received an application dated nil from Shri Om Parkash Chautal, MLA which is as under.

“Dear Sir

I am informa you that due to may illness. I am unable to attend the ensuing Session of Haryana Vidhan Sabha.

Yours sincerely.

Sd/

Om Parkash

Chautala

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महादेय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, आपकी और हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो सदन की मर्यादाएं हैं और जो नियम हैं उन सब को मानना चाहिए। माननीय सदस्य चौधरी औमप्रका । चौटाला

जी ने जो ऐप्लिके इन आपको भेजी है मैं पूछना चाहता हू कि उन्होंने यह एप्लीके इन किस रूल के तहत भेजी है और उसकी क्या जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष: कोई जरूरत नहीं है। परन्तु I have to inform the House, Please take your seat (Interruptions)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय चौटाला साहब अगर कहीं हमारी आवाज सुन रहे हो तो मैं आपके माध्यम से उनसे यह कहना चाहता हू कि उन्हें हाउस में आना चाहिए। हमने यह चौटाला देखा था जो रावण जैसा अहंकार से भरा हुआ था और आदमी नहीं समझता था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, अब आप अपनी सीट पर बैठे। (विघ्न)

डा सु गील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। (विघ्न)

Mr. Speaker: Please do not disturb. I have not allowed any body to speak (Interruptions) I have not allowed him.

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, प्वांयट आफ आर्डर पर प्वांयट आफ आर्डर नहीं होता। ये खुद संसद सदस्य रहे हैं इसलिए इन्हें ये सारी बातें तो पता होनी चाहिए।

Mr. Speaker: Is it the pleasure of the House that the leave of absence be granted to Shri Om Parkash Chautala,

MLA to remain absent during the current Budget Session of Haryana Vidhan Sabha.

Question is

That permission for leave of absence be granted.

The motion was carried

(iii) सचिव द्वारा

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker:: Now, the Secretary will make announcements.

सचिव: महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाले विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2005 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ—

1. The Haryana Appropriation (No .1) Bill, 2005.
2. The Haryana Appropriation Vote on Account (No .2) Bill, 2005.
3. The Haryana Staff Selection Commission (Repeal) Bill, 2005.

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker:: Now, the Parliamentary

Affairs Minister will move the motion under Rule 121 for the suspension of Rule 30.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Speaker Sir, I beg to move-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Business be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, 9th June, 2005.

Sir I also move-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Business be suspended and Government Business be transacted on 9th June, 2005.

Mr. Speaker: Motion move-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Business be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, 9th June, 2005.

And also-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Business be suspended and Government Business be transacted on 9th June, 2005.

Mr. Speaker: Question is-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Business be suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, 9th June, 2005.

And also-

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Business be suspended and Government Business be transacted on 9th June, 2005.

**बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पे 1
करना**

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, now I report the time table of the various Business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee meet at 12.30 P.M. on Thursday, the 9th June, 2005 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in session, shall meet on Monday at 2.00 P.M and adjourn at 6.30 P.M. Tuesday, Wednesday, and Friday will meet at 9.30 A.M and adjourn at adjourn at 12.30 P.m without question being put.

The Committee also recommends that the business on Monday, 20th June, 2005, the Assembly shall meet at 2.00 P.M and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of business for the day.

The Committee after some discussion also recommends that the business on 9th to 13th to 17th September, 2005, be transacted by the Sabha as follows:-

Thursday, the 9 th June, 2005 (2-00 P.M)	1	Oath/affirmation
	2.	Obituary Referecnes

	3	Question Hour.
	4.	Motion under Rule 121 for suspension of Rule 30.
	5	Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee.
	6.	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	7.	Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final reports thereon.
Monday the 13 th June, 2005 (2-00 P.M)	1	Question Hour.
	2	General Discussion on Budget Estimates for the 2002-2003

Tuesday, 14 th June, 2005 (2-00 P.M)	1.	Question Hour.
	2.	Papers to be laid, if any
	3.	Resumption of General discussion on Budget Estimates for the year 2005-2006
Wednesday, the 15 th June, 2005 (2-00 P.M)	2.	Question Hour.
	2.	Resumption of General discussion on Budget Estimates for the year 2005-2006 and reply by the Finance Minister thereon.
	3.	Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2005-2006
Thursday, the 16 th June, 2005 (2-00 P.M)	1.	Question Hour.

	2.	Non official Business
Friday, the 17 th June June, 2005 (2-00 P.M)	1.	Question Hour.
	2.	The Hayana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2005-2006
Monday, the 20 th June, 2005 (2-00 P.M)	1.	Question Hour
	2.	Motion uder rule 15 regarding Non stop sitting
	3	Motion uder rule 15 regarding Non stop sitting
	4.	Legilative Business
	5.	Any other Business.”

Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) Sir, I beg to move-

That the House agree with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee

Mr. Speaker: Motion moved-

That the House agree with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee

Mr. Speaker: Question is-

That the House agree with the recommendation contained in the First Report of the Business Advisory Committee

The motion was carried

सदन के मेज पर रखे गए पुन रखे गए कागज

Mr. Speaker: Now, a Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) Sir, I beg to lay on the Table-

The Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Ordinance, 2005 (Haryana Ordinance No. 1 of 2005)

The Haryana Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2005 (Haryana Ordinance No. 2 of 2005)

The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Ordinance, 2005 (Haryana Ordinance No. 3 of 2005)

Sir, I beg to lay on the Table-

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O 45/ H.A 9/1979/S. 8/2004, dated the 29th April, 2004, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) second amendment Rules, 2004, as required under section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Education Department Notification No. S.O 22/ H.A 12/1999/S. 24/2004, dated the 20th February, 2004, regarding the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2004, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Education Department Notification No. S.O 67/ H.A 12/1999/S. 24/2004, dated the 11th August, 2004, regarding the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2004, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The Parliamentary Affairs Department Notification No. S.O 153/ H.A 9/1979/S. 3 and 8/2004, dated the 1st October, 2004, regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) second amendment Rules, 2004, as required under section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

Sir, I beg to lay on the Table-

The Town and Country Planning Department Notification No. DS-11-05/4737 dated the 23rd May, 2005,

regarding the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendemet) Rules, 2004, as required under section 24(3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1995.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O 38/H.A 6/2003/S. 60/2005 dated the 26th May, 2005 regarding the Haryana Value Added Tax (Amendemet) Rules, 2004, as required under section 60 (4) of the Haryana Value Added Tax Act, 1995.

The Personeel Department Notification No. G.S.R 37/Const/Art320/2004 dated 14th December, 2004 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Fujnctions) Amendment Reuglation, 2004, as required uner Article 320(5) of the Consitution of India.

The Personeel Department Notification No. G.S.R 38/Const/Art320/2004 dated 14th December, 2004 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Fujnctions) Amendment Reuglation, 2004, as required uner Article 320(5) of the Consitution of India.

The Annula Report on the working of Hayana, Public Service Commission for the year 2002-2003, as required uner section 323(2) of the Consitution of India.

The 4th Annual Report of Uttar Haryana Bijli Virtan nigam Limited for the year 2002-2003, as required uner section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 6th Annual Report of Uttar Haryana Bijli Virtan nigam Limited for the year 2002-2003, as required uner section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 30th Annual Report of Uttar Haryana Bijli Virtan nigan Limited for the year 2003-2004, as required uner section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The 36th Annual Report of Uttar Haryana Bijli Virtan nigan Limited for the year 2002-2003, as required uner section 619-A(3) (b) of the Warehousing Corporations Act, 1956.

The Annula Report of Chaudhary Chara Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 2000-2001, as required uner section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultrual Universities Act 1970.

The Annula Report of Chaudhary Chara Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 2001-2002, as required uner section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultrual Universities Act 1970.

The 29th Annual Report of Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited, for the year 2002-2003, as required uner section 619-A(3) (b) of the Warehousing Corporations Act, 1956.

The 30th Annual Report of Uttar Haryana Bijli Virtan nigan Limited for the year 2003-2004, as required uner section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

वर्ष 2005-06 के बजट अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2005-06.

वित्त मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामय सदन में वर्ष 2005-06 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

1. प्रारम्भ में, मैं आपके सम्मानित सहयोगियों स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिन्दल तथा स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र सिंह के आकस्मिक एवम दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। इनके निधन से हरियाणावासियों के हृदय कम्पित हो जाये जो रिक्त स्थान पैदा हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति करना कठिन है।

2. मैंने 23 मार्च, 2005 को चालू वर्ष के प्रथम तीन मास के सरकार के खर्च को पूरा करने के लिए लेखानुदान की प्राप्ति हेतु एक अन्तरिम बजट प्रस्तुत किया था। अब मैं सदस्यों के विचारवर्ष एवम अनुमोदनार्थ वर्ष 2005-06 के लिये राज्य सरकार का पूर्ण बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आर्थिक स्थिति

3. माननीय सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 1991 में केन्द्र में कांग्रेस सत्तारूढ़ होने के बाद तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह, जो अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, ने प्रमुख ढांचगत आर्थिक सुधार भूरी किये, जिनको बाद में देश में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भी सराहना की गई। परिणामस्वरूप, देश निरन्तर प्रगति करते हुए आर्थिक समुदाय द्वारा भी सराहना की गई। परिणामस्वरूप, देश निरन्तर प्रगति करते हुए आर्थिक ताकत और स्थिरता की गई ऊँचाईयों पर पहुँचे गया है। हरियाणा राज्य में आर्थिक उदारीकरण

के लाभो को सचित करके अपने आर्थिक आधार को सुदृढ किया है।

4. मैने लेखानुदान प्रस्तुत करते हुए कहा था यूपीए सरकार द्वारा मई, 2004 में केन्द्र में सतारूढ होने के बाद अपनाये गये नये विकास पथ, जिसमें मानव संसधान विकास और जन साधारण के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया गया था, से राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को नई नीति मिली। राष्ट्र स्तर के आर्थिक परिदृश्य से राज्य अछूते नहीं रह सकते। माननीय सदस्यों को पहले से ही वितरित हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें राज्य की समय आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, इस तथ्य का साक्षी है। इसमें दर्शाया गया है कि स्थिर मूल्यों 1993-94 पर हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई यह वर्ष 2002-03 में 36.834 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2003-04 में 39993 करोड़ रुपये हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2003-04 में 39.993 करोड़ रुपये हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2003-04 में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में कृषि समेत प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 29.6 प्रतिशत रहा, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 27.8 प्रतिशत और 42.6 प्रतिशत रहा। सेवा क्षेत्र के हिस्से में निरन्तर वृद्धि इस बात का सूचक है कि अर्थ व्यवस्था यही दिशा में आगे बढ़ रही है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

बरहवा वितायोग

6. बारहवे वित्तयोग की सिफारिशों से वर्ष 2005-10 तक की पांच वर्षों की अवधि के दौरान राज्य अर्थ व्यवस्था पर महत्वपूर्ण पड़ेगा। आयोग के दृष्टिकोण से पता चलता है कि हरियाणा जैसे बेहतर वित्तीय प्रबन्धन वाले राज्यों को जनसंख्या, आय और कर प्रयासों जैसे मापदण्डों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिये पुरस्कृत करने के प्रयास नहीं किये गये हैं। केन्द्रीय करों के हरियाणा के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है और यह 0.944 प्रति शत, जैसा कि ग्यारहवें वित्तयोग में सिफारिश की थी, से बढ़ाकर 1.075 प्रति शत हो गया है इसी प्रकार कुल हस्तान्तरण में भी हरियाणा के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है और यह 0.967 से बढ़ाकर 1.064 हो गया है। मैं इस गरिमामय सदन को सूचित करना चाहूंगा कि हमारे राज्य को आयोग द्वारा अन्य राज्यों के लिये सिफारिश किये गये घाटानुदान तथा शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए उन्नयन अनुदान से वंचित रखा गया है। हमने इस मुद्दे पर अपनी चिन्ता पहले ही व्यक्त कर दी है और भविष्य में भी कहते रहेंगे कि हमें जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला।

7. बारहवें वित्तयोग ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य को चाहिए कि वह वित्तीय राजकोशीय लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक राजकोशीय उत्तरदायित्व कानून बनाये ताकि वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे का समाप्त किया जा सके और वर्ष 2009-10 तक राजकोशीय घाटे को कम करके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रति शत स्तर पर लाया जा सके। आयोग ने राज्यों के लिये दो ऋण राहत योजनाओं की भी सिफारिश की है और इन दोनों योजनाओं का लाभ उठाने के लिये राजकोशीय

उत्तरदायित्व कानून के निर्माण को आवश्यक पूर्ण भातें बनाया गया है वर्ष 2005-10 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान दोनो योजनाओ के अन्तर्गत हरियाणा को देय कुल वित्तीय लाभो की राशि ₹ 1029.70 करोड रूपये बनती है।

वार्षिक योजना 2005-06

8. माननीय सदस्यो को याद होगा कि मैने लेखानुदान प्रस्तुत करते समय इस गरिमामय सदन को सूचित किया गया था कि पिछली सरकार ने राज्य के चहुमुखी विकास के लिए व्यापक दीर्घकालिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया। हमे संसाधनो मे वृद्धि और धन का पुन आंबटन करने के लिये कठोर परिश्रम करना पडा ताकि हम भविश्य मे सतुंलित विकास की रूपरेखा तैयार करने मे सक्षम हो सके। हमे यह भी सुनिश्चित करना पडा कि हमारी प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओ की पूर्णत पूर्ति हो। हमने समानता और सामाजिक न्याय के साथ सतुंलित विकास की अपनी नीति के अनुरूप वर्ष 2005-06 के लिये 3000 करोड रूपये का योजनागत परिव्यय निर्धारित किया है, जो वर्ष 2004-05, के 2236,72 करोड रूपये के सतुंलित परिव्यय के मुकाबले 34 प्रतिशत अधिक है। परिव्यय मे यह रिकार्ड वृद्धि है। इस परिव्यय को भारत के योजना आयोग ने 19 मई, 2005 को मुख्यमंत्री महोदय के साथ हुई एक बैठक मे पहले अनुमोदित कर दिया है।

9. हमारे सरकार ने सामाजिक सेवाओ और भौतिक आधारभूत संरचना के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। तदनुसार, सामाजिक सेवाओ और भौतिक आधारभूत संरचना के

विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। तदनुसार, सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिये 1352.96 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जो योजनागत परिव्यय का 45.10 प्रतिशत है। इसमें समाज कल्याण के लिये 442 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। वयोवृद्धि नागरिकों, विकलांगों, विधवाओं और निराश्रितों की पेंशन पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि इनके प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। जलापूर्ति और स्वच्छता के लिये 280 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और तकनीकी शिक्षा समेत शिक्षा के लिये 279.66 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य सेवाओं के लिये 102 करोड़ रुपये, भाहरी विकास के लिये 90.89 करोड़ रुपये तथा महिला एवम बाल विकास कार्यक्रमों के लिये 26 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

10. आधारभूत संरचना के विकास के लिये 1180.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कुल योजनागत परिव्यय का 39.34 प्रतिशत है। ऐसा करते समय 4.49 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करके बिजली उत्पादन, सम्प्रेषण तथा वितरण को प्राथमिकता दी गई है सिंचाई के लिये 393 करोड़ रुपये और सड़कों व सड़क परिवहन के लिये 338.20 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

11. अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि प्रस्ताविक निवेदन से आर्थिक विकास, गरीबी कम करने तथा मानव कल्याण के कार्यों को पर्याप्त गति मिलेगी।

हमारी प्रथमिकताएँ

12. माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि हरियाणा के लोगों ने परिवर्तन, नये नेतृत्व, नई नीतियां और जनसाधारण, जो हमारी सरकार के राजनैतिक दर्शन का केन्द्र बिन्दु है, के कल्याण के लिये मत दिया था। हमारा परम कर्तव्य है कि हम लोगों को स्वच्छ एवम कल्याणकारी भासन प्रदान करके उनमें विश्वास की भावना पैदा करें, जिसमें उन्हें भय, आतंक और असुरक्षा से राहत मिलेगी। हमने भासन काल की बागडोर संभालते ही प्रदेश में व्याप्त अराजकता की समस्या का समाधान किया और प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया कि वह राज्य में शांति व सुव्यवस्थित वातावरण कायम करें। हम लोगों में विश्वास पैदा करने में सफल हुए हैं। भय की भावना धीरे धीरे समाप्त हो रही है।

13. हरियाणा विधानसभा के हाल ही तीन उप चुनावों में पार्टी को भारी बहुमत से मिली रिकार्डतोड़ ऐतिहासिक जीत से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि हरियाणा के लोगों को हमारी प्रगतिशील नीतियों में गहरी आस्था है।

14. हमारी सरकार गरीब व किसान हितैशी है और हम किसानों के मुद्दों पर सर्वेदन शीला के साथ विचार करने की नीति में विश्वास रखते हैं। हमें भासन की बागडोर संभालते ही भारी वर्षा और ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को हुए नुकसान के लिये किसानों को राहत प्रदान करने की समस्या से दो चार होना पड़ा। ऐसा महसूस किया गया कि फसलों के नुकसान के लिये राहत प्रदान करने के वर्तमान मानदण्ड बिल्कुल अपर्याप्त हैं। परिणामस्वरूप, इनमें गेहूं की फसल के लिये 50 प्रतिशत और

अन्य फसलों के लिये 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई तथा प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिये तत्काल 54.82 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। यही नहीं, हमने फरवरी, 2005 में हुए फसली नुकसान के लिये भी किसानों को इसी ऊंची दर से मुआवजा प्रदान किया। वर्ष 2005-06 के लिये आपदा राहत कोश की वार्षिक राशि में पर्याप्त वृद्धि करके इसे 124.37 करोड़ रुपये कर दिया गया। हमें आशा है यह है कि राशि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी।

15. साथ ही, सार्वजनिक उद्देय के लिये अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिये दिया जाने वाला मुआवजा निर्धारित कर दिया गया है, जिसकी न्यूनतम दर गुडगांव में 15 लाख रुपये प्रति एकड़, पंचकूला तथा चण्डीगढ़ के निकट के क्षेत्रों में पांच लाख रुपये प्रति एकड़ होगी। इससे लोगों को न्याय मिलेगा और सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिये उचित मुआवजा दिये जाने की उनकी मांग भी पूरी हो जायेगी। इस उपाय से किसानों को काफी राहत मिलेगी और विभिन्न न्यायिक अदातलों में मुकदमेबाजी में भी कभी आयेगी, जिस पर किसानों का काफी धन और समय खर्च होता है। यह हमारे चुनावी आवासनों में से एक था और मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हमने इस वायदे को पूरा कर दिया है।

16. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार समझौते और बातचीत की नीति में विश्वास रखती हैं। सरकार ने किसानों के बिजली के बकाया बिलों के सर्वेदन मिल मुद्दे के समाधान के

लिये मेरी अध्यक्षता मे एक समिति गठित की है। हमारी सरकार सता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त मे वि वास रखती है। ग्राम विकास समितियों जैसे अंसवैधानिक संस्थाओ को भंग करके पंचायती राज संस्थाओ जैसे सवैधानिक संस्थाओ की स्वयतता बहाल की गई है।

17. सतलुज नहर योजक नहर एस0वाई0एल0 हमारी सिचाई नीति का केन्द्र बिन्दु है सरकार इस नहर के निर्माण कार्य को भीघ्न पूरा करवाने तथा नदी जल मे राज्य के हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए वचनबद्ध है हम यह सुनिश्चित करेगे कि राज्य के साथ अन्याय न हो। हमारी सरकार पंजाब समझौता निरस्तीकरण अधिनियम, 2004 की भर्त्सना करती है और सरकार का दृढ वि वास है कि यह हमारे न्यायोचित हिस्से का पानी राज्य मे लाये जाने के मार्ग मे बाधा नही बनेगा।

18. राज्य के सभी क्षेत्रो को पानी का समान व न्यायोचित वितरण करना वर्तमान सरकार की एक अन्य प्राथमिकता है हमने पानी की कमी वाले हरियाणा के दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिमी भागो को अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाने के लिये कदम उठाये है। इसके अतिरिक्त हमने तेजी से हो रहे भाहरीकरण के कारण गुडगांव मे हुई पानी की कमी को पूरा करने हेतू गुडगांव व मानेसर की पेयजल सप्लाई मे वृद्धि करने के लिये एक योजना भुरु की है।

19. हमारी सरकार भाहरी स्थानीयो निकामो की वितीय स्थिति सुदृढ करने के लिए उत्सुक है हमने भाहरी आधारभूत

संरचना के विकास के लिये विशेष धनराशि निर्धारित की है। भाहरी नवीनकरण मिशन गठित करने का श्रेय डा० मनमहोन सिंह के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को जाता है। इस मिशन के तहत देश में कुछेक बड़े भाहरो को विशेष सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस परजियोना के प्रथम चरण में ऐसे महानगरो के रूप में फरीदबाद का चयन किया गया है लेकिन मुख्यमंत्री के प्रयासों से हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि अम्बाला और रोहतक को भी उन भाहरो की सूची में शामिल किया जाए, मुख्यमंत्री के प्रयासों से अम्बाला को शामिल कर लिया गया है। जिनकी इस कार्यक्रम के तहत आधारभूत संरचना के उन्नयन तथा रख रखाव के लिए अलग से पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि कई कई महीनों से म्यूनिसिपल कमेटियों के अन्दर मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं दी गई थी और न पेंशन दी गई थी। इस साल अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि सारे के सारे एरियर्स को खत्म कर देंगे।

20. शिक्षा वर्तमान सरकार के लिये प्राथमिकता का एक अन्य क्षेत्र है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक माडल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव है लगभग 3 करोड रूपया एक स्कूल पर खर्च होगा जो उच्चकोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा। जैसाकि माननीय सदस्यों ने समाचार पत्रों में पढा है कि प्रस्ताविक **राजीव गांधी एजुकेशन सिटी** जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म वस्तु निर्माण प्रौद्योगिकी नैनो टेक्नोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न विषयों में विविध स्तरीय शिक्षा प्रदान करके हरियाणावासियों के लिये श्रेष्ठ शिक्षा के एक केन्द्र

के रूप में कार्य करेगी और यह शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों में एक मील का पत्थर साबित होगी। अच्छी शिक्षा हमारे छात्रों को बेहतरीन नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनायेगी।

21. हम अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप सभी रोजगार सृजन योजनाओं को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं ताकि राज्य युवकों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध हो सके। सस्ती दर पर ऋण देने की योजनाओं के साथ-साथ कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में मजदूरी आधारित तथा स्व-रोजगार के अवसरों की तलाश की जा रही है। सरकार विदेशों में रोजगार से सम्बन्धित सूचना तथा सहायता प्रदान करने बारे निर्णय लेने के लिये एक विदेशीय रोजगार ब्यूरो तथा उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करेगी इस समिति को प्लेसमेंट करने का और बच्चों को बाहर भजने का तथा उन्हें सुविधा देने का पूरा अधिकार होगा। बेरोजगारी भत्ते के लिये पात्रता मानदण्डों को भी तर्कसंगत बनाया जायेगा 100 रूपये का भत्ता पिछली सरकार ने किया था उस समय हमने कहा था कि 100 रूपये का भत्ता पढ़े लिखे नौजवानों को देना उनके साथ मजाक है और भत्ते में समुचित वृद्धि की जायेगी ताकि जरूरतमंदों को कुछ ठोस आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। इसमें कोई मजाक नहीं है।

22. तीव्र और बेहतर सड़क संयोजना हमारी सरकार की प्राथमिकता का एक अन्य क्षेत्र है। राजीय सड़कों पर यातायात का भार कम करने के लिये निर्माण संचालन हस्तारंभ बी0ओ0टी0 आधार पर कुण्डली मानेसर पलवल सुपर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है। इस प्रकार, हमने

एन0सी0आर0 मे राष्ट्रीय राजधानी के साथ बेहतर संयोजना उपलब्ध करवाने के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है कि दिल्ली मेट्रो रेलवे का गुडगाव, कुण्डली, बहादुरगढ तथा फरीदाबाद तक विस्तार किया जाये। ताकि आगे फिरोजपुर झिरका तक पहुच जाये।

16.00 बजे

23. हमे प्रदे 1 मे कम हो रहे लिंगानुपात पर गरही चिन्ता है। कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी ढंग से अंकु 1 लगाने के लिये पूर्व प्रजन्न निदान तकनीकी पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 मे समुचित सं गोधन किया गया है। तथापि, मात्र अधिनियम मे सं गोधन किये जाने से इस सामाजिक बुराई का पूर्णतः उन्मूलन नही हो पायेगा। इसलिये, गैर सरकारी संगठनो, सामाजिक एवम धार्मिक संगठनो तथा लोगो के सक्रिय सहोयग से लिंगानुपात संतुलन बारे जागरूकता पैदा करने के लिये एक भा वत अभियान भुरु किये जाने की आव यकता है। लोगो मे लिंग संवेदन गीलता पैदा करने के लिए दूसरी लडकी पैदा होने पर माता पिता को पांच वर्ष के लिए 5000 रूपये प्रति वश्र की वित्तीय सहायता देने तथा जिस परिवार मे एकामात्र संतान लडकी हो, उसे पें ान देने जैसी प्रोत्सान आधारित विभिन्न योजनाये भुरु करने का प्रस्ताव है और अभी किसी निश्कर्ष पर नही पहुचे है। मेरी मुख्यमंत्री जी से और दूसरे साथियो से बात हुई है हम यह भी चाहते है कि हमारी इन योजनाओ का जो सही रूप से अनुकरण करेगा तो उन कन्याओ को भविश्य मे रिजर्वे ान देने का भी विचार है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 33 प्रति ात

महिलाओं की रिजर्वे इन स्कूल अध्यापकों में सुनिश्चित की है। यह कदम उठाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। इससे महिलाओं का सामाजिक विकास होगा। मुझे विश्वास है कि हम इन प्रयासों से लड़की को समाज में उसका उचित स्थान दिलवाने में कामयाब होंगे ताकि लड़की परिवार के लिये निधि समझी जा सके।

24. मुझे यह घोशणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा की महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रेरित करने हेतु श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से जींद में एक नया राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने महिलाओं के आर्थिक विकास की दिशा में एक अन्य कदम उठाते हुए महिला सहाकारी विकास बैंक स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका प्रबन्धन और संचालन केवल महिलाओं द्वारा किया जायेगा। समाज कल्याण के क्षेत्र में अनेक नई योजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें कुर्सी बुनकरों के रूप में कार्यरत नेत्रहीन व्यक्तियों का मासिक अनुसरक्षण भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, अत्यधिक विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेनशन भी 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जातियों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के विवाह पर 5100 रुपये की बजाय स्कीम 15000 रुपये की राशि देने की योजना शुरू की गई है, जिसे इन्दिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह भागुन योजना कहा जायेगा।

25. हमारा प्रयास होगा कि कृषि क्षेत्र को पुनर्गठित कृषि आधारभूत संरचना, फसलों के विविधिकरण जैव प्रौद्योगिकी

के प्रयोग बेहतर अनुसंधान एवम विकास सुविधाओं तथा कृषि उपज के लिये सुनिश्चित विपणन सहायता के द्वारा और ज्यादा लाभदायक बनाया जाये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों के सृजन से भाहरी क्षेत्रों की और पलायन करने की समस्या पर अकुंठित लागेगा। केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार आने वाले वर्षों में कृषि ऋणों में पर्याप्त वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है। हम किसानों के लाभार्थ इस दायित्व का निर्वाह करने के प्रयास करेंगे।

26. कर्मचारियों का कल्याण भी वर्तमान सरकार की एक अन्या प्राथमिकता है। कर्मचारियों की विकायतो के प्रति हमारा दृष्टिगत सहानुभूतिपूर्ण है। कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भवन निर्माण ऋण, विवाह ऋण तथा वाहन खरीदने के लिये दिये जाने वाले ऋण की राशि में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

27. राज्य सरकार अपने स्वतन्त्रता सेनानियों को भी सर्वाधिक सम्मान देती है, जिन्होंने हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिये अपने वर्तमान का बलिदान दे दिया। हमने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिये स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पे नान 1400 रूपये प्रतिमास से बढ़ाकर 3500 रूपये प्रतिमास कर दी है।

28. राजकोशीय अनुभासन तथा अनुत्पादक खर्च पर अकुंठित लागना हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। हमने भासन की बागडोर सम्भालने के तुरन्त बाद राज्य के

ऋण भार का सज़ान लिया और वित्तीय विवेक की लता के लिये भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिससे हमें विशेष प्रोत्साहन के रूप में 55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिली। इसके अतिरिक्त हमारे राजकोशीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाब देही और स्थिरता लाने के लिये विधानसभा के इसी सत्र में एक राजकोशीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध विधेयक लाया जा रहा है। यह कानून भविष्य में राज्य सरकार को घाटे व ऋण भार में कमी का मार्ग अपनाने के लिये प्रतिबद्ध करने के अतिरिक्त एक विवेक की ल राजकोशीय नीति के निर्माण में नीति निर्धारक का मार्गदर्शन भी करेगा। इस कानून से राज्य सरकार को कन्द्रीय ऋणों के पुनर्निर्धारण की वजह से बकाया ऋणों पर कम ब्याज दर के रूप में भारी राहत मिलेगी। इसके अलावा, अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

29. अपने राजस्व आधार में बढौतरी करना, स्थापना खर्च पर अकुलाना लगाना और उधार को केवल वित्तीय पूंजीगत खर्च तथा प्राथमिकता के क्षेत्रों में निवेश तक सीमित रखना, हमारी सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। हमने प्रदेशों में लाटरी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, जो प्रदेशों के सामाजिक ढांचे को तबाह कर रहा था। हमने किसान और व्यापारी समुदाय के हितों के साथ समझौता किये बिना मूल्य संवर्धन कर वैट प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है। हाल ही में घोषित हमारी आबकारी नीति से भाराब की नीलामी में एकाधिकार को समाप्त करने में मदद मिली है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि

हुई है। हमारी नई नीति की सफलता चालू वित्त वर्ष के दौरान हुई राजस्व बढ़ोतरी से झलकती है, जो पिछले कुछ वर्षों की कुल बढ़ोतरी से भी अधिक है इसी प्रकार, राज्य के विभिन्न भागों में खानों और खदानों की हाल ही में की गई निलामी से भी राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये सब तथ्य राज्य की वर्तमान नीति, जो पारदर्शी, तर्कसंगत और निष्पक्ष है, में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

30. उपाध्यक्ष हमने विभिन्न प्लान स्कीमों के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृति करने की वित्तीय भावितियों पर प्रासन्निक सचिवों को हस्तांतरित की है ताकि इस कार्य में होने वाली देरी से बचा जा सके। इससे विभागों को काफी राहत मिलेगी तथा वे अपनी नीतियों को और ज्यादा तत्परता से लागू कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, हमने निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सरकार की पुरानी खरीद नीति का त्याग कर दिया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि हम सरकारी धन का विवेकपूर्ण आंशिकरण करने के लिये अपनी वित्तीय स्थिति का निरन्तर विश्लेषण और इसकी समीक्षा करते रहेंगे। मैं सरकार की इस में आपका स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारी केवल परिव्यय की बजाय उत्पादन में अधिक रूचि है, जबकि पहले परिव्यय में रूचि रखने की परिपाटी थी। हम अपनी नीतियों के आम आदमी तक लाभ पहुंचाने और उनसे जनसाधारण को हुई सतुष्टि में रूचि रखते हैं। हमने इसके लिये परफार्मेंस आडिट प्रणाली शुरू कर दी है और इंजीनियरिंग विभागों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये बाहरी एजेंसी नियुक्त करने का प्रयास रखा है।

31. हम उपरोक्त नीतियों का अनुसरण करने अपने राजस्व खाते में पर्याप्त अधि रेश सृजित करने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले वर्षों में हमारे योजनागत परिव्यय के लिये उपयोग में लाये जायेंगे।

32. अब मैं अपनी विकास गतिविधियों के कुछेक प्रमुख क्षेत्रों पर विचार विमर्श करना चाहूंगा, जिन्हें वर्ष 2005-06 की योजना में प्राथमिकता दी गई है।

बिजली उपलब्धता में वृद्धि

33. बिजली को अर्थ व्यवस्था के विकास की धुरी समझा जाता है। तदनुसार हम राज्य में सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को सुनिश्चित, भरसक और किफायती बिजली सप्लाई देने के लिये वचनबद्ध हैं।

34. हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपनी बिजली उत्पादन क्षमता में बढोतरी करने, सम्प्रेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ करने और बिजली निगमों के कामगाज में सुधार लाने के लिये ठोस प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में 180 करोड़ रुपये के निवेश से उच्च वोल्टेज वितरण, प्रणाली, कृषि लोड को ग्रामीण घरेलू लोड से अलग करने जैसे योजनायें तथा आई0टी0 इनिशिएटिव समेत आधुनिकीकरण के कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। हमारी प्राथमिकता केन्द्रीय बिजली उत्पादन स्टेतों और स्वायत्त बिजली उत्पादकों के साथ दीर्घकालिक बिजली परियोजना समझौते करके राज्य की स्थापित क्षमता में वृद्धि करना

है। राज्य में निकट भविष्य में एक गैस आधारित बिजली उत्पादन स्टे पान करने का भी हमारा प्रयास होगा।

35. माननीय सदस्यों को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि आगामी लगभग दो वर्षों में यमुनानगर ताप पर बिजली घर परियोजनाया से 600 मैगावाट बिजली पैदा होने से राज्य में बिजली की स्थिति में काफी सुधार होगा। हिमाचल प्रदेश, तथा उत्तरांचल के साथ और सुयंक्त पन बिजली परियोजनाये स्थापित करने के भी प्रयास किये जायेगा।

36. जैसाकि मैंने कहा है कि हमारी सरकार राज्य के बिजली उपभोक्ताओं की जायज शिकायतों का समाधान करने लिये उत्सुक है। हमने काफी समय से लम्बित बिजली के बकाया बिलों तथा बिजली निगमों के पुररूद्धार व इसकी वित्तीय स्थिति सुधारने समेत अन्य मुद्दों में त्रिपूर्ण समाधान ढूढने के लिये एक कैबिनेट सब कमेटी पहले ही गठित कर दी है।

37. हमारी सरकार ने राज्य में नवीकरण ऊर्जा के संरक्षण व इसके कुशल प्रयोग के लिये भी अनेक उपाय किये हैं हम सरकारी भवनों, उद्योगों, होटलों, अस्पतालों, महाभोज हॉलों, जेल बैरकों, कैटीनों, आवासीय परिसरों, शिक्षा संस्थानों, पर्यटन केन्द्रों, इत्यादी में सौर ऊर्जा प्रणाली के प्रयोग को बढ़ावा देंगे।

वर्ष 2005-06 में, नवीकरणीय ऊर्जा समेत बिजली क्षेत्र के लिये कुल 1708.21 करोड रूपये का परिव्यय रखा गया है।

जल संसाधनों में वृद्धि

38. हमारी सरकार किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने के लिये वचनबद्ध है। राज्य में भूमिगत जल संसाधनों के उपयोग की सम्भावनाएँ बहुत सीमित हैं। हमारी सरकार जल संरक्षण और इसके समान व न्यायोचित वितरण पर अधिक बल देती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान सिंचाई चैनलों की मरम्मत व उनका आधुनिकीकरण करने, राजवाहों की क्षमता बढ़ाने, नई नहरों और चैक डैम्स का निर्माण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने तथा राज्यों के भूशक क्षेत्रों, विशेषतः दक्षिणी भागों के जल संचयन के लिये विभिन्न नालों के फालतू बरसाती पानी को लाने की भी हमारी योजना है।

39. सरकार सिंचाई प्रणालीकी त्वरित गति से मरम्मत व विस्तार करने के लिये ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोश आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नाबार्ड से धन ले रही है। नाबार्ड ने 697.62 करोड़ रुपये की लागत वाली 585 सिंचाई, ड्रेनज तथा जल संचयन योजनाएँ स्वीकृत की हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान, नाबार्ड से वित्त घोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिये 76 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2005-06 में, सिंचाई क्षेत्र के लिये कुल 922.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सड़क एवम पुल सुरक्षित एवम गति मील जीवन का आधार

40. सडके आर्थिक विकास के लिये एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। हरियाणा में 23.162 किलोमीटर लम्बी पी0डब्ल्यू0डी0 सडको का काफी बड़ा नैटवर्क है, जबकि वर्ष 1965 में राज्य के गठन के समय इनकी लम्बाई केवल 5110 किलोमीटर थी। यातयात में वृद्धि और अपर्याप्त रख रखाव के कारण हमारी वर्तमान सडको की हालत खराब हो रही है, इसलिये, हमारी सरकार वर्तमान सडको की हालत खराब हो रही है, इसलिये हमारी सरकार वर्तमान सडक तंत्र के सुधार, उन्नयन एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण कार्य निर्माण संचालन हस्तांतरण बी0ओ0टी0 आधार पर करवाने को प्रस्ताव है। यह सडक नैटवर्क की एक प्रमुख परियोजना है, जिसके अन्तर्गत एन0सी0आर0 का काफी क्षेत्र आयेगा और यह परियोजना आधारभूत संरचना की बेहतर सुविधाओं के माध्यम से समृद्धि लायेगी। हमारा बहादुरगढ़ से पंजाब सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 10 समेत राष्ट्रीय राजमार्गों को सुदृढ़ बनाने का भी प्रस्ताव है। हमारे द्वारा जाहजरानी, सडक परिवहन तथा राजमार्ग को सुदृढ़ बनाने का भी प्रस्ताव है। हमारे द्वारा जहाजरानी, सडक परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह किये जाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 1 पर पानीपत में और राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 2 पर बदरपुर में चिरप्रतीक्षित उत्थापित राजमार्गों एलिवेटिड हाईवे का निर्माण कार्य कुछेक महीनों में शुरू हो जाने की सम्भावना है।

41.अध्यक्ष महोदय, सडक तंत्र के समुचित रख रखाव के सम्बन्ध में हमारी चिन्ता के दृष्टिगत वर्ष 2005-06 में सडको के

रख रखाव के प्रावधान मे 141.92 करोड रूपये की रिकार्ड वृद्धि की गई है।

42. हमारा चाणक्वपुरी, नई दिल्ली मे स्टेट गैस्ट हाउस का निर्माण कार्य जो पिछले कई वर्षों से लम्बित है को पूरा करने का प्रस्ताव भी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान चण्डीगढ मे अतिरिक्त एम0एल0एफ0 फ्लैट्स का निर्माण करने का भी हमारा प्रस्ताव है।

वर्ष 2005-06 मे, सडको और भवनो के लिय कुल 636.20 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है।

परिवहन तन्त्र का आधुनिकीकरण

43. अध्यक्ष महोदय, तेज गति से आर्थिक विकास के लिये एक कुशल सडक परिवहन तन्त्र का होना आवश्यक है। राज्य के बस बेडे मे 3265 बसे है, जो प्रतिदिन 11.28 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है और इनमे 11.19 लाख यात्री सफर करते है। हमारी सरकार का बस सेवाओ के स्तर मे सुधार लाने के लिये नई पहलकदमी करने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान, राज्य के बस बेडे मे 600 से अधिक नई बसे भामिल करने का प्रस्ताव है।

44. माननीव सदस्यो को यह जानकर प्रसन्नता होगी की हम वर्तमान बस अडो और कर्मचालाओ के नवीकरण तथा पुनर्निमाण पर विशेष रूप से ध्यान देगे, जिसके लिये चालू वित्त वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष के दौरान कैथल, ढांड, बरवाला और पटौदी मे बस अडो के नये भवनो का

निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा और भूना, नारनौल तथा बहल से बस अड्डों के भवनो का निर्माण शुरू किया जायेगा। हमारा पिपली, रोहतक, और झज्जर के बस अड्डों को अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव है। एक अग्रणी कार निर्माता कम्पनी ने हरियाणा में एक अत्याधुनिक मोटर वाहन ड्राइविंग स्कूल स्थापित करने की पेशकश की है। जिससे, हमें आता है, सड़क यातयात काफी अनुपासन आयेगा।

वर्ष 2005-06 में, सड़को परिवहन के लिय कुल 691.02 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है।

पेयजल प्रति व्यक्ति आपूर्ति में वृद्धि

45. राज्य सरकार को अपने प्रत्येक गांव में पेयजल उपलब्ध करवाने का गौरव प्राप्त है। अब हम प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। दिसम्बर, 2004 से किये गये ताजे सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में पेयजल की कमी वाले 1971 गांव हैं, जंहा पेयजल की उपलभयता 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से कम है।

वर्ष 2005-06 में, ऐसे 840 गांव की पेयजल आपूर्ति में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

46. मेवात क्षेत्र में 1503 गांवों को पर्याप्त उपलब्ध करवोन का एकमात्र स्रोत यमुना के तल में स्थापित "रैनीवेल्ज" है क्योकि ज्यादातर स्थानीय पानी खारा है और पीने योग्य नहीं है। एन0सी0आर0 योजना बोर्ड ने 205.91 करोड रूपये की लागत

की मेवात रैलीवैल्ज योजना स्वीकृत की है। इस योजना पर पहले ही कार्य भुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त एन0सी0आर0 योजना बोर्ड ने फरीदाबाद, गुडगांव, पानीपत, रिवाड़ी, रोहतक, झज्जर तथा सोनीपत जिलो के ग्रामीण क्षेत्रो के लिये भी 162.10 करोड रूपये की लागत की एक पेयजल सवर्धन योजना अनुमोदित की है। हमारी भाहरी क्षेत्रो की पेयजल आपूर्ति मे भी सुधार लाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2005-06 मे, जन स्वास्थ्य के लिये कुल 690.33 करोड रूपये का परिव्यय रखा गया है।

कृशि क्षेत्र का विविधिकरण एवम आधुनिकीकरण

47. हरियाणा मुख्यतः एक कृशि प्रधान राज्य है, क्योंकि इसकी 75 प्रति ात जनंसख्या कृशि तथा सम्बद्ध गतिविधियो पर निर्भर है। इसलिये, हमारी सरकार अनुसंधान, विस्तार और विपणन सुविधाओ समेत सहायक सेवाओ पर वि ेश ध्यान देते हुए कृशि से सुव्यवस्थित विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

48. वर्ष 2005-06 के लिये 135.73 लाख टन खाधान्नो के उत्पाद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गन्ना, कपास और तिलहनो के लिये उत्पादन लक्ष्य क्रम ा: 9.90 लाख टन गुड 21.00 लाख गाठे तथा 12.03 लाख टन निर्धारित किया गया है।

49. अध्यक्ष महोदय, राज्य की वर्तमान फसल पद्धति की पृष्ठभूमि मे भूमि की उपजाउ भाक्ति को बनाये रखने और प्राकृतिक संसाधानो को ह्रास को रोकने के लिये फसलो का

विविधिकरण अत्यन्त आवश्यक है। हमने किसानों को फसलों बारे शिक्षित करने के लिए विशेष चेतना अभियान शुरू किया है। परन्तु हम महसूस करते हैं कि यदि किसानों को वैकल्पिक फसलों से ज्यादा आय सुनिश्चित नहीं की जाती है तो फसलों का विविधिकरण सफल नहीं हो सकता।

50. पशुपालन ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि करने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। राज्य सरकार द्वारा दुधारू पशुओं की आनुवंशिकी में सुधार लाने और उन्हें रोग मुक्त रखने के लिये महत्वकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसानों को उनके घर द्वारा पर ही पशु चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिये 198 नये पशु चिकित्सा संस्थान हास्पिटल्स पाली क्लिनिक्स बनाये जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2005-06 के दौरान, सोनीपत तथा भिवानी में ऐसे दो पाली क्लिनिक्स तथा पंचकूला में पालतू जानवरों के लिये एक पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

51. राज्य के लोगों ने मछली पालन को आय के एक वैकल्पिक साधन के रूप में अपनाया है। इसलिये, हमारी सरकार मछली पालन को बढ़ाया देने की ओर उचित ध्यान देगी। प्रति हैक्टेयर मछली उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है। वर्ष 2005-06 के दौरान, हमने 2500 लाख मछली बीज का भण्डारण करने और 48000 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

52. अध्यक्ष महोदय, वन पर्यावरण सतुलन बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी सरकार वृक्षारोपण को उच्च प्राथमिकता देती है। इस समय राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.4 प्रतिशत भू भाग पर वन तथा वृक्ष हैं। ग्रामीण और स्थानीय लोगों के सक्रिय सहयोग से सामुदायिक वानिकी और फार्म वानिकी के अन्तर्गत गांव की भामलता भूमि और निजी भूमि पर गहरा वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2005-06 में, कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं के लिये कुल 690.33 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

नई उद्योग नीति

53. अध्यक्ष महोदय, हरियाणा अपनी भानदार आधारभूत संरचना, निवेश के लिये आदेशों का वातावरण, श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच अच्छे सम्बन्धों तथा सहायकों व प्रोत्साहनपूर्ण नीतिगत ढांचे की वजह से देशी व विदेशी निवेशकों की पहली पसन्द के रूप में उभारा है।

54. सुधार अवधि के दौरान शुरू की गई निजीकरण व भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं तथा व्यापार व उद्योग को दिये गये प्रोत्साहनों से देश में निवेश तथा निर्यात को बढ़ाया मिला है। चालू वर्ष के दौरान, हरियाणा की निर्यात 20000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो जाने की सम्भावना है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिये जिला गुडगांव के गांव गढी हरसल में एक विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने का प्रस्ताव है। कुण्डली मानेसर पलवल एक्सप्रेस मार्ग एच0एस0आई0डी0सी0 द्वारा

बनवाने की हमारी योजना है। यह राज्य की सबसे बड़ी सड़क परियोजनाओं में से एक होगी। एक्सप्रेस के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र विकसित करने का हमारा प्रयास है। पानीपत में वर्तमान तेल भाँधक कारखाने के चारों ओर पैट्रो कैमीकल केन्द्र विकसित करने का भी हमारा प्रस्ताव है।

55. हरियाणा अपने सुदृढ औद्योगिक आधार पर उन्नत बुनियादी ढाँचे के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक आदर्श स्थल बन गया है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये हमारी सरकार का वस्त्र के लिये पानीपत में, मोटरगाड़ियों के लिए गुडगाँव में तथा हल्के इंजीनियरिंग सामान के लिए फरीदाबाद में तीन औद्योगिक परियोजना समूह विकसित करने का प्रस्ताव है। हमारा भारत सरकार के सहयोग से केन्द्रीय प्लास्टिक तथा इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए प्रस्ताव है। हमने राज्य में खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबन्धन संस्थान स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार आग्रह किया है।

56. सेवा क्षेत्र में तीव्र के दृष्टिगत तथा राज्य औद्योगिकीकरण को और बढ़ावा देने के लिये हमारी सरकार ने अपनी नई उद्योग नीति 2005 घोषित कर दी है। हमारी औद्योगिकी नीति का मूल उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों उच्चकोटी के बुनियादी ढाँचे के निर्माण, रोजगार के नये अवसर सृजित करने तथा निवेशकों के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने पर विशेष बल देते हुए प्रदेश का संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना है। बुनियादी ढाँचाग्रस्त परियोजनाओं में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देने तथा बड़ी परियोजनाएँ

आकर्षित करने के लिये नये औद्योगिक नगर विकसित करने पर विशेष बल दिया जायेगा। इस नीति के तहत कृषि आधारित खाद्य प्रसस्करण उद्योग तथा साफ्टवेयर विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वस्त्र वैज्ञानिक उपकरण इत्यादि जैसे अन्य प्राथमिकता के क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की हमारी प्राथमिकता होगी।

वर्ष 2005-06 में, औद्योगिक प्रोत्साहन सेवाओं के लिये कुल 64.15 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

रोजगार तथा व्यावसायिक शिक्षा

57. अध्यक्ष महोदय, बढ़ती बेरोजगारी राज्य के सामाजिक ढांचे के लिये गंभीर खतरा बनती जा रही है। सरकारी नौकरियों सीमित हैं और बड़ी संख्या में युवक महसूस करते हैं कि उनका भविष्य अनिश्चित है। इसलिये, हमारी सरकार राज्य के युवकों को लाभादायक रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये वचनबद्ध है।

58. बेरोजगारी भते की वर्तमान योजना, जिसमें समस्या के समाधान पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है, को तर्कसंगत बनाने का हमारा प्रस्ताव है। हम विदेशों में रोजगार दिलवाने की प्रणाली शुरू करेंगे और प्रमुख औद्योगिक भाहर गुडगांव, फरीदाबाद, सोनीपत तथा यमुनानगर में निजी रोजगार सेवाएँ उपलब्ध करवाएँगे।

59. हमारी सरकार राज्य में औद्योगिक क्षेत्र तथा मानव संसाधन विकास के प्रयासों के बीच तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता महसूस करती है। हमारा उद्देश्य उद्योग और व्यापार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्चकोटी की तकनीकी जन शक्ति उपलब्ध करवाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य के ऐसे विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित करने की हमारी योजना है जहां पहले से ऐसे संस्थान कार्यरत नहीं हैं। पांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में श्रेष्ठता केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ताकि विशिष्ट ट्रेडों में उच्चकोटी की दक्षता उपलब्ध करवाई जा सके। सरकार द्वारा के तकनीकी संस्थानों के उन्नयन में निजी भागीदारी की सम्भावना का पता लगाने के लिये हाल ही में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

शिक्षा एवम खेल

60. अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास के लिये उच्चकोटी की शिक्षा अति आवश्यक तथापि, जैसाकि मैंने अन्तरिम बजट भाषण में कहा था कि इस क्षेत्र में गुणवत्ता और आधारभूत संरचना की कमी है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिये बिना शिक्षा संस्थानों का निर्बाध गति में विकास हुआ है। इसलिये, हमारी सरकार सबके लिये प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने, शिक्षा सुविधाओं के विस्तार और हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष बल देती है।

61. इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में दाखिल करवाने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। हमने सरकारी स्कूलों के 50000 प्रतिभाशाली छात्रों को पुरस्कृत करने हेतु शिक्षा में श्रेष्ठता के लिये राजीव गांधी छात्रवृत्ति नामक एक नई योजना शुरू की है। यह एक अनूठी योजना है, जिसका उद्देश्य बच्चों के दाखिला में वृद्धि करना, प्रतिभावाने छात्रों को सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित करना, लड़कियों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिये प्रेरित करना और छात्रों में एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना पैदा करना है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये केन्द्र द्वारा वित्त पोषित सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।

62. शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाने के लिये भौक्षणिक निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने, प्रणाली मूल्यकांन प्रणाली शुरू करने तथा लोगों को सक्रिय भागीदार सुनिश्चित करने जैसे विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान को वित्तीय दृष्टि में आत्मनिर्भर संस्थान बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। स्कूली छात्र कम्प्यूटर दक्षता विकास कार्यक्रम एन0सी0आर0 तथा चण्डीगढ़ के सीमावर्ती जिलों में लागू करने का प्रस्ताव है। सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को डैस्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। राज्य में प्रत्येक जिले में एक मांडल स्कूल खोलने का भी प्रस्ताव है।

63. जहां तक खेलों की बात है हमारी सरकार खेलों और युवा कल्याण गतिविधियों को बढ़ाया देने पर विशेष ध्यान

देगी। हरियाणा को उत्कृष्ट खिलाड़ी पैदा करने का गौरव प्राप्त होता है। भारीरूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित करने की एक नई योजना लागू करने का हमारा प्रस्ताव है ताकि उनमें विवास और अनुशासन की भावना पैदा हो सके। हमारी सभी युवा क्लबों को पुनः सक्रिय करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें गांव में युवा गतिविधियों के एक केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सके। खेलों को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों की कुशलता में सुधार लाने के तौर तरीके सुझाने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

वर्ष 2005-06 में, शिक्षा खेलों, कला और संस्कृति के लिये कुल 2180.69 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यहां तक नौबत आ गई थी, अभी चार दिन पहले 50 बच्चे मुझे आकर मिले और कहने लगे कि हमें बचाओ। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। वे कहने लगे कि हम खेल के झूठे सर्टिफिकेट देकर पिछली सरकार के समय नौकरी लगे थे। अब लग गये तो हमें क्यों निकाल रहे हो। इस तरह की अनियमितताएं पिछली सरकार के समय में हुई हैं।

समाज के कमजोर वर्गों का सामाजिक आर्थिक उत्थान

64. हमारी माननीय वयोवृद्ध नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों और समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है। हम महिलाओं और बच्चों के विकास और उनके स्तर में सुधार लाने पर भी बराबर रूप से ध्यान देंगे।

65. जैसाकि मैने अपने भाषण के भुरु मे जिकर किया है कि लिंगानुपात मे हो रहा असतुलन हमारे लिये एक गभीर चिन्ता का मामला है। प्रोत्साहन आधारित योजनाये लागू करने तथा स्कूली बच्चो मे जागरुकता पैदा करके लोगो की मानसिकता मे परिवर्तन लाये जाने की आव यकता है। अपने उद्दे ायो की प्राप्ति के लिये लिंग सवेदन णीलता प्र ि ाक्षण, कार्यक्रम, संचार तथा प्रचार, महिला मण्डलो को स्वयं सहायता गुपो मे परिवर्तित करने, सर्वोत्तम माता पुस्कार, महिलाओ के लिये खेल प्रतियोगिता तथा ग्रामीण कि णेरियो के लिये पुरस्कार इत्यादि की विभिन्न नई योजनाये भुरु करने का हमारा प्रस्ताव है।

वर्ष 2005-06 मे, इस क्षेत्र के लिये कुल 737.79 करोड रूपये का परिव्यय रखा गया है।

स्वास्थ्य सेवाओ मे सरकारी निजी हिस्सेदारी

66. अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण सकेतम है। इसलिये हमारी सरकार हरियाणा के लोगो के स्वास्थ्य मे सुधार लाने के लिये प्रतिबद्ध है।

67. हमारी सरकार स्वास्थ्य के बुनियादी ढाचें के विकास पर विशेष बल दे रही है। हमारा इरादा राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रो मे आधुनिक उपकरण, पर्याप्त मात्रा मे दवाईया तथा अन्या बुनियादी सुविधाये उपलब्ध करवाने का है। हम वर्तमान अस्पताल भवनो के समुचित रख रखाव के लिये प्रयासरत है, जिसके लिये चालू वर्ष के बजट मे पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

68. प्रदेश में 24 घण्टे प्रसूति सेवायें तथा आपतकालीन प्रसूति सेवायें उपलब्ध करवाने के लिये पहली अप्रैल, 2005 से प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आर0सी0एच0-11 का द्वितीय चरण शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, फलवता दर इत्यादि जैसे स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाना है।

69. वर्ष 2005-06 के दौरान, नई विभिन्न स्वास्थ्य योजनायें शुरू करने का हमारा प्रस्ताव है। ताकि प्रदेश में उच्चकोटि की पर्याप्त स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों अथवा भाहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों, विशेषतः किसान और श्रमिकों जो दिन के समय अपने खेतों और कार्य स्थल पर व्यस्त रहते हैं, को नई योजना मार्गदर्शिका आधार पर शुरू की जायेगी। हमारा सस्थागत प्रसूति के लिये 300 गांवों में प्रसूति हट्स स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को चलती फिरती चिकित्सा यूनिटों तथा बहु विशेषज्ञता स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से पूरा करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2005-06 में, चिकित्सा शिक्षा तथा वैकल्पिक पद्धति समेत स्वास्थ्य सेवाओं के लिये कुल 468.29 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

ग्रामीण विकास एमव पंचायते

70. हमारी सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में गहरी रुचि है। इसलिये, हम ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा इसके उन्नयन पर विशेष बल देते हैं। साथी ही ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करने तथा रोजगार के अवसर जुटाने के लिये राज्य तथा केन्द्र द्वारा वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित की जा रही है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व रोजगार योजना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत स्व रोजगार के सभी पहलू आते हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान, इस योजना पर 16 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाती। राष्ट्रीय सम विकास योजना पिछड़े जिलों के लिये एक नई योजना है, जिसके लिये धन की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है।

71. वर्ष 2005-06 के दौरान, विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं का विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। पंचायती राज संस्थाओं को उनके प्रासंगिक और वित्तीय अधिकार दिये गये हैं ताकि वे विकास प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें। और प्रजातांत्रिक प्रणाली सुदृढ़ हो सकें। द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों जिन पर राज्य सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, पर लिये जाने वाले निर्णय के अनुसार इन निकायों को और ज्यादा कार्यों तथा भाक्तियों का हस्तांतरण किया जायेगा।

वर्ष 2005-06 में, विभिन्न ग्रामिण कार्यक्रमों के लिये कुल 277.49 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

नगरपालिका प्रशासन और नगर विकास

72. अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका स्थानीय भासन की महत्वपूर्ण यूनिटे है इसिलये, हमारी सरकार भाहरी क्षेत्रो के समेकित विकास तथा भाहरी लोगो के कल्याण के प्रति भी उतनी ही चिन्तित है।

73. हमारी सरकार की नगरपालिकाओ की वित्तीय सुदृढ करने मे भी रूचि है, जिसके बिना ये कोई भी विकास कार्य नही कर सकती। वर्ष 2005-06 के दौराने बारहवे वित्त आयोग की सिफारि गो के अनुसार भाहरी स्थानीय निकायो को विकास कार्यों के लिये 18.20 करोड रूपये का वार्षिक अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा। भाहरी ग्रामीण मि ान के अन्तर्गत भाहरी स्थानीय निकायों को भाहरी बुनियादी ढांचा सुदृढ बनाने के लिये 47.30 करोड रूपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी। हम द्वितीय वित्त आयोग द्वारा सिफारि ा किये गये वित्तीय अन्तरण की जांच कर रहे है और इन निकायो को राज्य के बजट के तदर्थ आधार पर 50 करोड रूपये की राशि ा हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

74. हमारी सरकार भाहरी क्षेत्रो मे रहने वाले समाज के गरीब तथा कमजोर वर्गों के लोगो को बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत आवास तथा स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाने के लिये वचनबद्ध है।

वर्ष 2005-06 मे, भाहरी विकास की सेवाओ के लिये कुल 167.70 करोड रूपये का परिव्यय रखा गया है।

पारदर्शी एवम प्रभावी सेवा अन्तरण प्रणाली के लिये इलैक्ट्रानिक प्र ासन

75. सूचना प्रौद्योगिकी की राज्य के समाजिक आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिये, हमारी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास को अत्यधिक महत्व देती है। हमारी आई0टी0 इनिशिएटिव की प्रमुख प्राथमिकता पारदर्शिता तथा कुशल सेवा अनंतरण के लिये लोक केन्द्रीत सेवाये उपलब्ध करवाना है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश में प्रौद्योगिकी पार्कों व प्रौद्योगिकी नगरों की स्थापना के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है ताकि इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जा सके।

बजट अनुमान 2005-06

76. अध्यक्ष महोदय अब मैं इस गरिमामय सदन के सम्मुख वर्ष 2005-06 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

77. वर्ष 2005-06 में, भारतीय रिजर्व बैंक, के खाता अनुसार 215.97 करोड़ रुपये की राशि के घाटे के साथ आरम्भ हुआ और इसी 242.36 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने की सम्भावना है।

78. बजट अनुमान वर्ष 2005-06 के अनुसार इस वर्ष की 242.36 करोड़ रुपये के घाटे के साथ आरम्भ होने और 294.03 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार, वर्ष के दौरान हुआ लेन देन 51.57 करोड़ रुपये के घाटे को दर्शाता है।

79. वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों में राज्य के समेकित कोश में कुल प्राप्तियों 1613012 करोड़ रुपये की दिखाई गई है, जबकि गत वर्ष के संशोधित अनुमानों में ये 1576734 करोड़ रुपये की थी। प्रस्तावित बजट में 1613742 करोड़ रुपये का करोड़ रुपये का खर्च दिखाया गया है, जबकि वर्ष 2005-06 में, के संशोधित योजनाओं और अन्य विकास योजनाओं के लिये 394.48 करोड़ रुपये का परिव्यय के अतिरिक्त राज्य योजना के लिये 3000 करोड़ रुपये का परिव्यय का प्रावधान है।

80. वर्ष 2005-06 में, के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों 648.75 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 120327 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है, जबकि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों में ये 11388.52 करोड़ रुपये की थी। वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों में 12985 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च अनुमानित है, जो वर्ष 2005-06 में, के संशोधित अनुमानों में 1161432 करोड़ रुपये के खर्च से 1371.12 करोड़ रुपये अधिक है।

81. अध्यक्ष महोदय, हमने बजट घाटे को प्रबन्ध सीमा में रखा है और वित्तीय अनुपासन के लिये मेरे द्वारा प्रस्तावित उपायों से घाटे को नियन्त्रित करने में मदद मिलेगी। हमें आशा है कि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में सुधार के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान हमारे कर राजस्व में पर्याप्त वृद्धि होगी। इसलिये, बजट में नया कर लगाने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है। थपिंग मुझे आशा है कि हम अपने योजना कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करके प्रस्तावित योजनागत परिव्यय का पूरा उपयोग करने में सफल होंगे।

82. इस भाषण को समाप्त करने से पहले मैं वित्त विभाग तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों व कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस बजट प्रस्तावों को तैयार करने में मेरी सहायता की है।

83. महोदय अब मैं वर्ष 2005-06 के बजट अनुमानों को इस गरिमामय सदन के विचार तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

Mr. Speaker: Now, the House is adjourned till 2-00 P.M Monday, the 13th June, 2005.

17.02 Hours.

(The Sabha then adjourned till 2-00 P.M Monday, the 13th June, 2005.)